● वर्ष : 17 ● अंक : 196 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित गुरुवार 07 मई 2026

भारत-वियतनाम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ जीतेंगे : प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत-वियतनाम के बीच हुए 13 एमओयू, अब भारत की दवाइयों का एक्सेस बढ़ेगा
पीएम मोदी ने कहा-अब हम चम्पा सभ्यता की मनुस्क्रिप्ट को भी डिजिटलाइज करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध अब बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं और दोनों देश मिलकर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, और साथ जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच बुधवार को हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों और आपसी प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी अब और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-वियतनाम के बीच व्यापार पिछले दशक में दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों ने इसे 2030 तक 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दवाओं, कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनी है। बहुत जल्द, वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का और हम वियतनाम के डूरियन और पोमेलो का स्वाद लेंगे। दोनों देशों ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने के तहत भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर सहमति जताई। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, स्टेट-टू-स्टेट और सिटी-टू- सिटी सहयोग को भी बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। वियतनाम के सहयोग से भारत, आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध हैं। चम्पा सभ्यता के मंदिरों के संरक्षण और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण जैसे कदम इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत और वियतनाम तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं और नई रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से दोनों देश एक-दूसरे के विकास में सहायक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक-दूसरे के विकास में सहयोग करना ही दोनों देशों की साझा प्रगति का मार्ग है। भारत की पॉलिसी के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। हम अपनी सुदृढ़ होती हुई रक्षा और सुरक्षा सहयोग से रूल ऑफ लॉ शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति योगदान देते रहेंगे। वियतनाम के सहयोग से भारत, आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। भारत के संस्कृति मंत्रालय और वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय के बीच 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक और वियतनाम के स्टेट बैंक के बीच भुगतान प्रणालियों और डिजिटल भुगतान में नवाचार के क्षेत्र में सहयोग। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत औषधि प्रशासन के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग। मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम और हो ची मिन्ह सिटी पीपल्स कमेटी के बीच मित्रता और सहयोग की स्थापना पर एमओयू हुआ। वहीं आईसीसीआर और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड एजुकेशन-द दा नांग यूनिवर्सिटी के बीच आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज की स्थापना।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

जो जीता वही सिकंदर, जीत हमेशा ताकतवर की होती है

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया है। चुनाव लड़ने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तैयार कर लिया था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम-दाम-दंड-भेद, सभी संवैधानिक शक्तियां, टीएमएसी में अपने जासूस भेजने से लेकर वह सभी काम किया, जो चुनाव को जीतने के लिए जरूरी था। प्यार और युद्ध में सब जायज है। युद्ध और प्यार का एक ही लक्ष्य होता है, जीतना- जीतना। भाजपा के रणनीतिकार अच्छी तरीके से यह बात जानते हैं। चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। इसमें नैतिकता, नियम या कानूनों का कोई लेना-देना नहीं है। जब भगवान राम युद्ध के दौरान विभीषण और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा मारा गया, जैसी युक्ति अनैतिक लड़ाई जीतने के लिए अपना सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाजपा के ऊपर जो आरोप लग रहे है, वह सब जायज हैं।

यही कहा जा सकता है, जीतना ही प्रमुख लक्ष्य होता है। जो जीतता है, उसी के पास सत्ता होती है। जिसके पास सत्ता होती है, सारी शक्तियां उसी के नियंत्रण में काम करती हैं। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था। उस समय सभी नौ ग्रह रावण की कैद में थे। हनुमान जी नहीं होते, उन्होंने रावण की कैद से नौ ग्रहों को नहीं छुड़ाया होता, तो भगवान राम की जीत भी संभव नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गई है। ममता दीदी और उनकी पार्टी टीएमसी बुरी तरह से हार गई है। यही युद्ध का परिणाम है, जो जीता वही सिकंदर। इसके बाद अदालती और कोर्ट-कचहरी की लड़ाई लड़ते रहो, कुछ होने-जाने वाला नहीं है। जिसके पास सत्ता है, सारे ग्रह नक्षत्र उसी के ईशारे पर नाचेंगे। हारने वाले को यही ग्रह-नक्षत्र अपने इशारे पर नचायेंगे। पिछले कुछ वर्षों से यही होता हुआ दिख रहा है। कहा जाता है, लोकतंत्र में जनता मलिक होती है।

जनता का राज होता है, पिछले एक दशक से जनता चुपचाप बैठी है। सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए पदाधिकारी सरकार के इशारे पर, जनता को अपने ईशारों पर नचा रहे हैं। भय और लालच से वशीभूत जनता चुपचाप तमाशा देख रही है। जब तक जनता में जागृति नहीं आयेगी, वह सत्ता के आगे गुलाम बनी रहेगी। जब जनता को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख जाएगी, तब जाकर वह स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करेगी। अभी तो जनता सत्ता के ऊपर निर्भर है। भाजपा जानती है, कैसे भी चुनाव जीतो और सत्ता पर काबिज हो जाओ। सत्ता की ताकत जब तक होगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पिछले कुछ समय से भारत में यही देखने को मिल रहा है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च, एक प्लेटफॉर्म से ही निपटेंगे सभी काम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
सत्यमेव जयते

नई दिल्ली। देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया। यह पहल 10वें नेशनल समिट ऑन इनोवेशन एंड इन्क्लूसिविटी के दौरान किया गया। यह पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया गया है और आभा से जुड़कर मरीजों के हेल्थ डेटा का सुरक्षित आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह पोर्टल अलग-अलग स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बिखरे सिस्टम को एक साथ जोड़कर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। अब तक कई ऐप और पोर्टल अलग-अलग काम कर रहे थे, जिससे डेटा दोहराव और समय की बर्बादी हो रही थी। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ भारत पोर्टल के जरिए एक ही जगह पर सभी डेटा एंट्री संभव होगी, कई लॉगिन की जरूरत खत्म होगी और रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग आसान होगी। इसके साथ स्वास्थ्य कर्मियों को राहत- आशा, एएनएम, सीएचओ और मेडिकल ऑफिसर्स को अब अलग-अलग सिस्टम पर काम नहीं करना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म से ही सभी काम निपटेंगे, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। मंत्रालय के मुताबिक इससे इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में 20–30 प्रतिशत तक कमी, डेटा एंट्री और स्टाफ दोहराव में 20–40 प्रतिशत तक कमी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज आएगी।

पंजाब में हुए हमले पर मान सरकार के आरोपों को भाजपा ने बताया निंदनीय

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने पंजाब में धमाकों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने बुधवार को कहा कि भगवंत मान सरकार से पंजाब की सुरक्षा हो नहीं रही और अपने नौसिखिएपन का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। 22 ग्रेनेड हमले, मिसाइल अटैक, पिछले चार वर्षों में पंजाब की मिट्टी अपने बेटों के खून से लाल हुई, लेकिन मान साहब, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बेहद शर्मसार, निंदनीय और अशोभनीय है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। सीमावर्ती प्रांत होने के नाते राज्य में सुरक्षा को लेकर चिंता है। नशे में डूबा पंजाब संकट में पहुंच चुका है। कभी रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया जा रहा है, कभी सेना के कैंपों के आसपास धमाके, पंजाब में लगातार हो रहे धमाके और हमलों ने साबित कर दिया है कि भगवंत मान की सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। तरुण चुग ने कहा कि पंजाब की जनता को कहानियां और चुटकुले नहीं, शांति, सुरक्षा और विकास चाहिए। मौजूदा हालात साफ बता रहे हैं कि आप सरकार पंजाबियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल है। इसके साथ ममता बनर्जी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तरुण चुग ने कहा कि ममता बनर्जी को ईवीएम मुख्यमंत्री बनाए तो सब ठीक है लेकिन अगर जनता उन्हें हरा कर सजा दे तो ईवीएम खराब है।

राज्यपाल को सीएम सरमा ने अपना इस्तीफा सौंपा, नई सरकार के गठन का मार्ग साफ

एजेंसी। गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया, इससे नई सरकार के गठन का मार्ग साफ हो गया। विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन का औपचारिक मार्ग प्रशस्त कर मुख्यमंत्री सरमा ने राजभवन में राज्यपाल आचार्य से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सरमा के साथ रानोज पेगू और मानव डेका सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया कि मंत्रिपरिषद का इस्तीफा भी सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मौजूदा सरकार को नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रशासन के रूप में काम जारी रखने का निर्देश दिया है। अगले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वे अंतिम निर्णय लेने वाले है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि 11 मई के बाद नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की निश्चितता नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को होगा या नहीं।

विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भारत जापान के बीच हुए कई अहम समझौते

एजेंसी। नई दिल्ली

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को भारत और जापान के बीच समझौता किया गया है। इसके लिए जापान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति मंत्री ओनोडा किमी ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार किया गया। यह समझौता जापान एजेंसी फॉर मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुआ। इसके अलावा, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के कैबिनेट ऑफिस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 में जापान यात्रा के बाद भारत-जापान विज्ञान एवं तकनीक साझेदारी एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है।

दोनों देशों की ताकत का मेल : उन्होंने कहा कि जापान के पास उन्नत तकनीक है, जबकि भारत के पास युवा और कुशल मानव संसाधन की बड़ी ताकत है। दोनों मिलकर नई तकनीकों में तेजी से नवाचार कर सकते हैं। जापान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति मंत्री ओनोडा किमी ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक इस्तेमाल की सराहना की। उन्होंने भारतीय युवाओं में नवाचार और असफलताओं से सीखने की क्षमता को भी खास बताया।

इस मौके पर क्वांटम और हेल्थ सेक्टर पर फोकस: बैठक में नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित संचार और हेल्थ रिसर्च जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

जब कोर्ट में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा वकील- मुझे माफ कर दीजिए मिलॉर्ड!

अमरावती। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब भड़क गए। सुनवाई के दौरान जस्टिस तर्लादा राजशेखर राव एक युवा वकील पर इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने उसे 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना सोमवार की है। जब कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस और पासपोर्ट जब्त किए जाने को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान जज मामले को स्थगित करने का मन बना रहे थे, तभी वकील और जज के बीच बहस छिड़ गई। जज ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या मैंने आपकी रिट याचिका खारिज कर दी है? आपको लगता है कि आप बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं? पुलिस को बुलाइए। अब तुम जाओ और अपील दायर करो। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वकील ने ऐसी क्या बात कही थी जिससे जस्टिस राव इतने नाराज हो गए। कोर्ट रूम में तनाव इतना बढ़ गया कि युवा वकील हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मिलॉर्ड।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

कोलकाता। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हो रही हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता के न्यूटाउन इलाके में मंगलवार को मधु मंडल नाम के भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंसा और

तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसको देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस के पुलिस आयुक्त तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने और स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है।

आईएमएफ ने माना, भारत को बढ़ाना होगा पेट्रोल-डीजल के दाम

एजेंसी। नई दिल्ली

अमेरिका-ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य बाधित होने से बीते कुछ समय से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। क्रूड के दाम में आए भारी उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट स्थिर बने हुए हैं। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को लगता है कि भारत के लिए ईंधन की कीमतों को लंबे समय तक दबाकर रखना मुश्किल होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) के एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कृष्ण श्रीनिवासन ने कहा कि भारत यदि सरकार लंबे समय तक बाजार की वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखती है, तब इससे 'मार्केट सिग्नल' यानी बाजार के असली संकेत गड़बड़ा जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब कीमतों को अपने हिसाब से चलने देना जरूरी होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। लेकिन भारत के लिए स्थिति और चिंताजनक है। 30 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का क्रूड बास्केट यानी कच्चे तेल की खरीद लागत करीब 118.70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। हाल ही में ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरियाई कार्गो जहाजों को निशाना बनाने की खबरों ने सप्लाई चेन पर खतरा बढ़ा दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में अफरा-तफरी का माहौल है।

सड़क मार्ग से नेपाल आने वाले वाहनों के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

एजेंसी। काठमांडू

नेपाल सरकार ने भारतीय पर्यटकों तथा भारत के रास्ते नेपाल आने वाले अन्य देशों के पर्यटकों के वाहन की प्रवेश सुविधा देने के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इस प्रणाली का उद्घाटन वित्त मंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ने एक कार्यक्रम के दौरान किया। कस्टम विभाग ने स्थल मार्ग से नेपाल में प्रवेश करने वाले विदेशी वाहनों के लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया है, जिससे वे ऑनलाइन ही अपना विवरण भरकर राजस्व भुगतान कर सकते हैं। नई प्रणाली लागू होने के बाद अब नेपाल में वाहन लेकर आने वाले भारतीय और तृतीय देश के पर्यटक ऑनलाइन ही अपनी जानकारी दर्ज करके शुल्क जमा कर सकते हैं। पहले ऐसे वाहनों को भन्सार नाके पर पहुंचकर भौतिक रूप से अस्थायी अनुमति लेनी पड़ती थी। यात्रा अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के लिए भन्सार नाके पर जाना पड़ता था या जुर्माना भरना पड़ता था, लेकिन अब पर्यटक घर से ही ऑनलाइन माध्यम से वाहन का परमिट भरकर और भुगतान करके बिना झंझट नेपाल यात्रा कर सकते हैं। नई सेवा का शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री डा. वाग्ले ने कहा कि इससे सीमा क्षेत्रों में पर्यटकों को होने वाली परेशानियां खत्म होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सुशासन और तेज, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवा देने की प्रतिबद्धता के तहत यह पहल की गई है। हम चाहते हैं कि पर्यटकों को कोई कठिनाई न हो और सरकारी सेवाएं तेज और सरल हों। भन्सार विभाग के महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी ने बताया कि अब नेपाल में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों के परमिट पूरी तरह डिजिटल हो गए हैं। यात्री और पर्यटक अब अपने वाहनों का विवरण ऑनलाइन स्वयं घोषित कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।नेपाल सरकार को देय राजस्व भी पर्यटक वाहन ऑनलाइन या बैंक काउंटर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने वाले वाहन भन्सार में अपने ईमेल पर प्राप्त क्यूआर कोड दिखाकर नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। विभाग के अनुसार यात्रा अवधि समाप्त होने पर पर्यटक नेपाल के भीतर से ही ऑनलाइन माध्यम से उसे बढ़ा सकते हैं।

भारत खुशकिस्मत है जिसे नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में इस बार ऐसा उलटफेर हुआ है जिसकी गूंज सात समंदर पार अमेरिका तक जा पहुंची। बंगाल में पहली बार बीजेपी की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी के 'किले' के ढहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को खास अंदाज में बधाई दी। ट्रंप ने इस जीत को 'ऐतिहासिक और निर्णायक' बताया है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि जिस राज्य में दशकों तक टीएमसी और वामपंथियों का बोलबाला था, वहां अब बीजेपी का परचम लहरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी को इस धमाकेदार जीत के लिए खुद मैसेज भेजकर बधाई दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि भारत खुशकिस्मत है जिसे मोदी जैसे पीएम मिले हैं। ट्रंप का ये खास संदेश साफ बताता है कि बंगाल की इस जीत की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बता दें 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार किया है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

स्वाती मालीवाल ने पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। पंजाब में हाल के घटनाक्रमों पर चिंता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा है। स्वाती मालीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पंजाब में एक ही दिन में दो संवेदनशील स्थानों पर धमाके हुए हैं। पिछले सप्ताह एक रेल ट्रैक पर भी विस्फोट की घटना सामने आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दिनदहाड़े गोलियां चलने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आती है। सांसद ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे गंभीर हालात के बावजूद मुख्यमंत्री विधायकों को बड़ी संख्या में बसों और गाड़ियों में भरकर दिल्ली लेकर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से अकेले मुलाकात की, जबकि अन्य विधायकों को अपने नाम की तख्ती पकड़ाकर बाहर धूप में खड़ा कर दिया।उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब विधानसभा में जहां कानून-व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, वहां मुख्यमंत्री भगवत मान कथित रूप से शराब पीकर आते हैं और बहकी बहकी बातें करते हैं। भाजपा सांसद स्वाती मालीवाल ने अंत में सवाल उठाया कि आखिर राज्य की स्थिति को इस तरह क्यों बिगड़ने दिया जा रहा है और सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है।

उत्तम नगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, 18 लोगों को आरोपित बनाया

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले में द्वारका कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में 18 लोगों को आरोपित बनाया है। कोर्ट ने इस मामले के शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। इस मामले में दो आरोपित अभी फरार हैं, जबकि दो नाबालिग आरोपितों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से केस चलेगा। करीब पांच सौ पन्नों की चार्जशीट में हत्या, गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होना, दंगा करने, अनाधिकृत रुप से प्रवेश करने और एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है। अब इस मामले की सुनवाई द्वारका कोर्ट के एससी-एसटी कोर्ट में होगी। दरअसल, चार मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तरुण के परिवार की एक नाबालिग लड़की ने 4 मार्च को पानी भरा बैलून एक महिला पर फेंका, जिसके बाद महिला के रिश्तेदारों ने तरुण भुटौलिया पर डंडों से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद तरुण की अगले दिन मौत हो गई। इस मामले में आरोपित मुस्लिम समुदाय का है, जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसके पहले दिल्ली नगर निगम ने इस मामले के एक आरोपित की संपत्ति के कथित रुप से अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त कर दिया था।

नांगलोई में अवैध एलपीजी रीफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, तीन आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बक्करवाला इलाके में अवैध एलपीजी रीफिलिंग और कालाबाजारी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 96 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस ट्रांसफर करने के उपकरण, तीन वाहन और तौल मशीनें बरामद की हैं। इस मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बुधवार को बताया कि, बक्करवाला रोड स्थित लक्ष्मी नगर इलाके में एक खाली प्लॉट में घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध तरीके से रीफिलिंग और भंडारण किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद विशेष टीम गठित कर छापा मारा गया। मौके पर एक नर्सरी के पीछे खाली प्लॉट में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पड़े मिले। कुछ सिलेंडर वहां खड़े तीन टेंपो में लोड थे। पुलिस ने मौके से सुल्तानपुरी निवासी 37 वर्षीय विनोद, नजफगढ़ निवासी 38 वर्षीय विजय और कंझावला निवासी 26 वर्षीय वंश राज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों गैस सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने बरामद सिलेंडरों को अवैध घोषित करते हुए जब्त कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी गैस एजेंसी से घरेलू एलपीजी सिलेंडर उठाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय उन्हें खाली प्लॉट में जमा कर लेते थे। इसके बाद भरे सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में अवैध उपकरणों की मदद से रीफिलिंग की जाती थी। फिर इन्हें खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता था। पुलिस के अनुसार, इस अवैध कारोबार से न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा था, बल्कि बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। जिस स्थान पर रीफिलिंग की जा रही थी वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और कभी भी आग या विस्फोट की घटना हो सकती थी। क्राइम ब्रांच ने आरोपितों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा गैस एजेंसी के अन्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं या नहीं।

महापौर ने सभी उपायुक्तों के साथ की बैठक, सफ़ाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बुधवार को सभी जोनल उपायुक्तों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जिसमे दिल्ली में सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए ठोस और प्रभावी कार्ययोजना पर जोर दिया गया। बैठक में महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जोन अपने-अपने क्षेत्रों में सफ़ाई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से और अधिक सुदृढ़ करें। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई जाती है, वहां संबंधित कूड़ा प्रबंधन प्राइवेट एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए| उन्होंने विशेष रूप से ज़ोन के सभी संवेदनशील स्थानों (वल्नरेबल प्वाइंट्स) की पहचान कर वहां नियमित और विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि जोन के सेनेटरी सुपरवाइजर (एसएस) और असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर (एएसआई) फील्ड में सक्रिय रूप से मौजूद रहकर सफाई कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि जमीनी स्तर पर प्रभावी सुधार दिखाई दे। सफाई कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए महापौर प्रवेश वाही ने एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा करते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और सफाई व्यवस्था में और सुधार आएगा।महापौर ने यह भी निर्देश दिया कि सभी सफ़ाई कर्मचारी अपनी वर्दी पहनकर कार्य करें, जिससे न केवल अनुशासन सुनिश्चित होगा बल्कि एमसीडी की सकारात्मक छवि भी मजबूत होगी। महापौर ने कहा कि रेहड़ी-पटरी को भी जागरूक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके ठेलों एवं दुकानों के आसपास सफाई बनी रहे तथा किसी भी प्रकार का कूड़ा न फैलाया जाए। बैठक में नालों की सफाई की भी विस्तृत समीक्षा की गई।प्रवेश वाही ने निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड सहित अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नालों की सफ़ाई का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि जलभराव की समस्या से समय रहते निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त महापौर ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और इस कार्य में दिल्ली पुलिस के सहयोग से प्रभावी अभियान चलाने पर जोर दिया। साथ ही अवैध मीट की दुकानों और अवैध डेयरियों के खिलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना निगम की पहली प्राथमिकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हम इस दिशा में मिशन मोड में कार्य करते हुए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण जवाबदेही, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें, ताकि नागरिकों को साफ़-सुथरा और बेहतर वातावरण मिल सके।

अबकी बार लोकतंत्र का अंतिम संस्कार: श्री पवन खेड़ा

, श्री पवन खेड़ा, अध्यक्ष, मीडिया और प्रचार (संचार विभाग), AICC का बयान

लोकतंत्र की शान ,ज़ीशान अली

'वोट-चोर' भाजपा सरकार ने अब बेशर्मी और सुनियोजित तरीके से असम और पश्चिम बंगाल की जनता के जनादेश को पलट दिया है। एक गहरी जड़ें जमा चुकी, रिमोट-कंट्रोल्ड चुनावी मशीनरी के ज़रिए, भाजपा ने उन संस्थाओं को प्रभावी ढंग से हाईजैक कर लिया है, जिनका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की रक्षा करना है। आज जो बचा है, वह व्यवहार में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि एक खोखला ढांचा है - जिस पर कब्ज़ा कर लिया गया है, जिसके साथ समझौता कर लिया गया है, और जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में, भाजपा पर जनादेश की बड़े पैमाने पर चोरी करने, चुनावी सूचियों में हेरफेर करने और 100 से ज़्यादा सीटों पर नतीजों को अपने हिसाब से गढ़ने का आरोप है। यह संस्थागत चुनावी लूट है। 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (INDIA गठबंधन) लोकतांत्रिक संकट के इस निर्णायक क्षण में ममता बनर्जी के साथ पूरी मज़बूती से खड़ा है। INDIA गुट को मज़बूत करने का उनका संकल्प एक व्यापक राष्ट्रीय अनिवार्यता को दर्शाता है - सुनियोजित तोड़फोड़ के खिलाफ संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करना। INDIA गठबंधन इस बात को मानने में एकजुट है कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि हेरफेर के ज़रिए थोपा गया एक मनगढ़ंत फैसला है। पश्चिम बंगाल में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (Special Intensive Revision) के दौरान, चुनावी सूचियों से चौंका देने वाले 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जबकि 27 लाख नागरिकों को किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखने का बुनियादी प्रक्रियात्मक अधिकार भी नहीं दिया गया। कम से कम 50 निर्वाचन क्षेत्रों में, हटाए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से भी ज़्यादा थी, जिससे घोषित नतीजे ढांचागत रूप से पहले से तय हो गए। यह सुनियोजित चुनावी इंजीनियरिंग है। असम और पश्चिम बंगाल अब सिर्फ़ दोषपूर्ण चुनावों के गवाह नहीं बन रहे हैं, बल्कि वे एक 'कब्ज़ा की गई' लोकतांत्रिक प्रक्रिया के गवाह बन रहे हैं।

शशि शेखर वेम्पति बने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शशि शेखर वेम्पति को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक शशि शेखर वेम्पति तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति प्रसून जोशी के पद छोड़ने के बाद की गई है। प्रसून जोशी को हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया है, जिसके चलते उन्होंने सीबीएफसी प्रमुख का पद छोड़ा। शशि शेखर वेम्पति मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लंबे अनुभव रखते हैं। इससे पहले वे प्रसार भारती के सीईओ भी रह चुके हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को आमतौर पर सेंसर बोर्ड के रूप में जाना जाता है, जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। यह चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रमाणित करता है। यानि देश में फिल्मों को प्रमाणित करने वाली प्रमुख संस्था है, जो यह तय करती है कि कोई फिल्म किस श्रेणी में रिलीज होगी।

साइबर स्लेवरी नेटवर्क का भंडाफोड़ : सीबीआई की नौ स्थानों पर छापेमारी, एक गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने साइबर स्लेवरी यानी भारतीय नागरिकों को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में साइबर अपराध सिंडिकेट्स के चंगुल में फंसाने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। एजेंसी ने इस मामले में देशभर में नौ स्थानों पर छापेमारी की और लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क भारतीय युवाओं को ऊंचे वेतन वाली नौकरियों का झांसा देकर म्यांमार और कंबोडिया स्थित ठिकानों पर भेजता था। वहां उन्हें कथित साइबर स्लेवरी कैंपों में रखा जाता था, जहां उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी कराई जाती थी। पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे और उन्हें शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। कई मामलों में पीड़ितों को परिवार से फिरौती दिलवाकर ही छोड़ा गया। एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा व सहारनपुर जिलों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। जांच में क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन का भी विश्लेषण किया गया है ताकि नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके।लखनऊ से गिरफ्तार आरोपित पर आरोप है कि उसने भारतीय नागरिकों को इन कैंपों तक पहुंचाने में मदद की। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नेटवर्क से जुड़े एजेंटों को विदेशी ठिकानों से भारतीय नागरिकों की सप्लाई के बदले भुगतान किया जाता था। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।

फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, मे डाक्टरों ने नवजात को दी नई जिंदगी, हृदय की कि सर्जरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल मे नवजात बच्चें को गर्भ मे ही दिल की गंभीर बीमारी हो गई जिस उसके माता-पिता दोनों डॉक्टर होने के कारण इसका सही उपचार के लिए कई जगह तलाश की, इंटरनेट पर फोर्टिस एस्कर्ट के डॉक्टर अय्यर की जानकारी मिली सम्पर्क किया और सही समय पर सही ईलाज हुआ यह कहना था नवजात के माता-पिता का। डॉक्टर अय्यर के बताया कि ,जन्म के समय नवजात का हृदय अखरोट जितना और हृदय को खून पहुंचाने वाली नसें लिवर से जुड़ी थीं। ऐसे में जन्म के तुरंत बाद उसके हृदय को रक्त न मिलने, लिवर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में रक्त भरने की आशंका के कारण जान का संकट बना हुआ था। हमारी टीम ने मिलकर जन्म के महज 15 मिनट के अंदर नवजात के हृदय की ओपन हार्ट जटिल सर्जरी करनी शुरू की और सात घंटे बाद उसकी जान बचा ली। चिकित्सकों का दावा है कि नवजात स्वस्थ है और उसे कोई परेशानी नहीं है। भारत में प्रत्येक दस हजार में से एक बच्चा ऐसे विकार के साथ जन्म लेता है, जिसका समय पर इलाज बेहद जरूरी होता है। पीडियाट्रिक कार्डियोलाजी के निदेशक डा.आशुतोष मारवाह ने बताया कि नवजात की सर्जरी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। निदेशक पिडियाट्रिक कार्डियाक इंटेसिविस्ट डा. पार्वती अय्यर ने बताया कि जन्म से पहले गर्भ में शिशु की स्थिति कई बार बनती-बीगड़ती रही पर,उसे संभाला गया। सर्जरी के बाद नवजात की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और करीब 11 दिनों में उसे स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

जमाअत ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव के बाद हुई हिंसा पर गंभीर चिंता जताई, सरकार से विकास के लिए एक समावेशी तथा जन-केंद्रित एजेंडा अपनाने का आग्रह किया

» जमाअत ने देश में बढ़ती महंगाई और हीटवेव का संकट पर भी चिंता व्यक्त की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के शीर्ष नेतृत्व ने हालिया राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है जिनमें विधानसभा चुनावों का आयोजन, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा, बढ़ती महंगाई और आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले प्रचंड हीटवेव का संकट शामिल है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के मुख्यालय में आयोजित मासिक प्रेस कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए जमाअत के उपाध्यक्ष मलिक मोअतसिम खान ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हाल ही में घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों पर बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ कुछ राज्यों में नई सरकारें सत्ता संभालने वाली हैं और कुछ में सरकारें दोबारा चुनी गई हैं, उन्हें शासन के प्रति एक समावेशी, ज़िम्मेदार और जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश इस समय आर्थिक संकट, बेरोज़गारी, बढ़ती महँगाई और शिक्षा, विकास तथा सामाजिक न्याय से जुड़ी समस्याओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है; जिनके लिए प्रतीकात्मक उपायों के बजाय तत्काल और ठोस ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे पश्चिम बंगाल में तत्काल कानून-व्यवस्था बहाल करें और राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मलिक मोअतसिम खान ने चुनावों के संचालन, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की । उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन से संबंधित रिपोर्टों, हाशिए पर पड़े समुदायों को मताधिकार से वंचित किए जाने के आरोपों और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का हवाला दिया। उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि चुनाव प्रचार के दौरान ध्रुवीकरण करने वाले नैरेटिव के इस्तेमाल ने लोकतांत्रिक माहौल को प्रदूषित कर दिया है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। अन्य राज्यों, विशेष रूप से असम में, धन-बल, दुष्प्रचार और विभाजनकारी भाषा के इस्तेमाल को लेकर भी इसी तरह की चिंताएँ जताई गईं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी प्रथाएँ लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करती हैं, और चुनावों में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही का आह्वान किया। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं की भूमिका को लेकर चिंताओं को उजागर करते हुए कहा कि किसी भी तरह के पक्षपात या संस्थागत कमज़ोरी की धारणा से जनता का विश्वास कमज़ोर होता है। उनका अवलोकन है कि जो पार्टियाँ धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का दावा करती हैं, वे आपसी फूट के कारण एकजुट मोर्चा बनाने में विफल रही हैं, जिससे विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला करने की उनकी क्षमता कमज़ोर हुई है। उन्होंने विपक्षी दलों से आह्वान किया कि वे सरकारों को जवाबदेह ठहराते हुए एक रचनात्मक और ज़िम्मेदार भूमिका निभाएँ तथा एक स्पष्ट, मुद्दों पर आधारित वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करें।

भाटी माइंस में 13 वर्षीय छात्र की गला घोंटकर हत्या, जंगल में मिला शव, दोस्तों संग खेलने निकला था

लोकतंत्र की शान

शांति सेवा न्याय
Delhi Police
SHANTI SEWA NYAYA

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में 13 वर्षीय छात्र की गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। छात्र मंगलवार शाम दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तलाश शुरू की तो उसका शव पास के जंगल क्षेत्र से बरामद हुआ। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस के अनुसार मृतक नौवीं कक्षा का छात्र था और परिवार के साथ भाटी माइंस क्षेत्र में रहता था। मंगलवार शाम वह रोज की तरह घर से दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था। देर रात तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। दक्षिजण जिले के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बुधवार को बताया कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आसपास के इलाकों के साथ जंगल क्षेत्र में भी तलाश की गई। इसी दौरान पुलिस टीम को पास के जंगल में छात्र का शव पड़ा मिला। शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। छात्र के दोस्तों, परिचितों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्र आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में दो नाबालिग आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।जिनसे पूछताछ की जा रही है।

कैंप में वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को दिया गया निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण : सत्या शर्मा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को उस्मानपुर वार्ड संख्या 226 स्थित कार्यालय में "वृद्धों व विकलांगों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कैंप" का आयोजन किया गया। इसमें जरूरतमंद वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण वितरण किया गया। इस कैंप के माध्यम से क्षेत्र के लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए, जिनमें कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कंधे एवं सर्वाइकल दर्द के लिए सपोर्ट बेल्ट, चलने में सहायता के लिए छड़ी, वॉकर एवं तीन पहियों वाली ट्राइसाइकिल, शौच के लिए कमोड सीट, सुनने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) तथा बैठने में असुविधा के लिए कुशन आदि शामिल रहे।इस अवसर पर स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि

उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनके जीवन को अधिक आसान बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा जनहित में इस प्रकार की योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और इस जनकल्याणकारी प्रयास के लिए स्थायी समिति अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।

विदेश राज्य मंत्री ने यूएन में कहा- प्रवासन पर भारत का 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण

लोकतंत्र की शान

न्यूयॉर्क। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच (आईएमआरएफ) के दौरान भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने प्रवासन के प्रति भारत के 'जन-केंद्रित' दृष्टिकोण पर जोर दिया, जो गरिमा, समावेशन और अधिकारों के सम्मान पर आधारित है। राज्य मंत्री ने सुरक्षित व नियमित प्रवासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (जैसे ई-माइग्रेट) के महत्व पर बात की और प्रवासन को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जोड़ने का आह्वान किया। सिंह ने कहा भारत ने सुरक्षित और नियमित प्रवासन को सुगम बनाने के लिए अब तक 23 देशों के साथ 27 प्रवासन और गतिशीलता समझौते किए हैं। ये समझौते श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हैं। विदेश राज्य मंत्री ने अपने संबोधन से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा मैंने भारत द्वारा सुरक्षित और नियमित प्रवासन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाना, कांसुलर सेवाओं को सुदृढ़ करना, प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को संपन्न करना तथा हमारे कुशल श्रमिकों के कौशल-विकास, प्रशिक्षण और प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण पर ज़ोर देना शामिल है। उन्होंने आगे कहा मैंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रवासन के प्रति हमारा दृष्टिकोण 'जन-केंद्रित' बना हुआ है, जो गरिमा, समावेशन और अधिकारों के सम्मान पर आधारित है। इस दौरान राज्य मंत्री ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की भूमिका की सराहना की। इसमें विशेष रूप से 'ई-माइग्रेट' पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस और स्किल इंडिया डिजिटल हब का उल्लेख किया गया, जो प्रवासन शासन में पारदर्शिता बढ़ाते हैं और श्रमिकों को शोषण से बचाते हैं। सिंह ने कौशल विकास को प्रवासन शासन की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा भारत अपने श्रमिकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स और प्रस्थान-पूर्व प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने जोर दिया कि प्रवासन एक 'मजबूरी नहीं, बल्कि एक विकल्प' होना चाहिए, जो अवसर और गरिमा द्वारा समर्थित हो। यूएन बैठक से इतर राज्य मंत्री ने इक्वाडोर गणराज्य के मानव गतिशीलता उप मंत्री साउल पाकुरुकु से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन, गतिशीलता साझेदारियों तथा आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। इससे पहले सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी श्रमिक मंत्री हंस लियो कैकडैक के साथ गतिशीलता और प्रवासन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा की।

संक्षिप्त समाचार

रामपुर शाहबाद पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता, सरकारी भवनों में चोरी करने वाले 4 शातिर चोर गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान , मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। जनपद में सरकारी भवनों को निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों के खिलाफ रामपुर शाहबाद पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें सोलर पैनल, बैटरियां, मदरबोर्ड, कंप्यूटर, एलईडी समेत अन्य कीमती उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा एडिशनल एसपी रामपुर अनुराग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी रात के अंधेरे में सरकारी भवनों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस टीमों को लगाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए सभी आरोपी संभल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ में कई अन्य चोरी की घटनाओं से जुड़े सुराग भी मिले हैं। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। एडिशनल एसपी अनुराग सिंह ने बताया कि पुलिस आगे भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। बाइट – अनुराग सिंह (एडिशनल एसपी रामपुर)

बाबा विश्वनाथ व काल भैरव के दरबार में माथा टेका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

» गोरक्षपीठाधीश्वर ने लोकमंगल और प्रदेश की खुशहाली की कामना की

» मंदिर में श्रद्धालुओं का किया अभिवादन, नन्हे-मुन्नों को भी दुलारा

वाराणसी। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह काशी पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा विश्वनाथ धाम व काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में माथा टेक कर पूजन-अर्चन किया। उन्होंने लोकमंगल और प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। बाबा काल भैरव मंदिर में मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। साथ ही आसपास के घरों में नन्हे-मुन्नों को दुलारा। काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने आए भक्तों ने मुख्यमंत्री को देखकर 'हर-हर महादेव' का जयकारा लगाया। मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु', विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. अवधेश सिंह, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री–मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री बुधवार सुबह बड़ा लालपुर स्थित चांदमारी निवासी राजीव कृष्ण के आवास पर पहुंचे। उन्होंने यहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर परिवारजनों को शुभकामनाएं दीं।

मोबाइल कोर्ट में 126 मामलों की सुनवाई दिव्यांगजनों को वितरित किया गया उपकरण

लोकतंत्र की शान : देवरिया। गांधी सभागार, विकास भवन देवरिया में उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। मोबाइल कोर्ट के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु स्टाल लगाए गए।इसके अतिरिक्त जिला पूर्ति विभाग द्वारा अंत्योदय एवं राशन कार्ड तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग पेंशन एवं सहायक उपकरण वितरण हेतु स्टाल लगाए गए थे।मोबाइल कोर्ट में राज्य आयुक्त द्वारा कुल 126 मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान मौके पर ही 09 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए, 27 आयुष्मान कार्ड तथा 22 राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। सुनवाई के दौरान एक राशन कार्ड तत्काल जारी किया गया। वहीं 03 मामले भूमि विवाद से संबंधित पाए गए, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।राज्य आयुक्त ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि सप्ताह में दो दिन दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। साथ ही मेडिकल बोर्ड में चिकित्सकों की संख्या 05 से बढ़ाकर 07 किए जाने तथा प्रत्येक तीन वर्ष में नए चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मोबाइल कोर्ट के दौरान 11 स्मार्ट केन, 03 लेप्रोसी किट, 10 श्रवण यंत्र, 12 बैसाखी एवं 15 ट्राइसाइकिल का वितरण भी किया गया।कार्यक्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी व उनकी टीम, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उपनिदेशक दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (गोरखपुर मंडल), जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, नायब तहसीलदार सदर, लीड बैंक मैनेजर, जिला सेवा योजन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला पूर्ति अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पांचवें दिन श्री कृष्णा बाल लीलाओं एवं गोवर्धन पूजा का वर्णन सुनाया गया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन पूज्या सिद्धि पूनम जी के श्री मुख से किया गया, वही पूतना वध, माखन चोरी, मिट्टी खाना, ब्रह्मांड दर्शन एवं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने और इंद्र के अहंकार को तोड़ना आदि का प्रसंग सुनाया गया वहीं गोवर्धन पूजा भी की गई और 56 भोग लगाया गया, कथा पंडाल में पंचम दिन भारी भीड़ नजर आई जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी, कथा वाचीका पूज्य सिद्धि पूनम जी ने कथा के बीच भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का प्रसंग सुनाते हुए महिलाओं को बताया कि पति परमेश्वर की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, वही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनकर भक्तगण भाव विभोर हो गए, तथा भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पंडाल ग उठा, वही कथा के प्रसंग के दौरान विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गई उपस्थित श्रद्धालुओं ने झांकियां पर पुष्प वर्षा भी की, इस अवसर पर मुख्य रूप से संदीप अग्रवाल मेडिकल वाले, पुनीत अग्रवाल, अंचल अग्रवाल, सुनीता आर्य, कविता शर्मा, उमा अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल, पृथ्वी, पारुल अग्रवाल, महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे।

हर जरूरतमंद का बनवाएं आयुष्मान कार्डः मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा और आश्वस्त किया कि सरकार इलाज कराने में भरपूर मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग-अलग मामलों के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद निस्तारण होना चाहिए। जनता दर्शन में हर बार की तरह बुधवार को भी कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, साथ ही भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। अस्पताल का एस्टीमेट मिलते ही विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर पीड़ा का निवारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए।

'नेशन फर्स्ट' हर नागरिक के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं: मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब लड़ाई सीमाओं से बढ़कर साइबर, स्पेस, डेटा नेटवर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक फैल चुकी है। पारंपरिक युद्ध कौशल के साथ-साथ अब तकनीकी दक्षता, रणनीतिक सोच और मानसिक दृढ़ता भी अनिवार्य हो गई है। आज के युद्ध में कीबोर्ड, सेटेलाइट और डेटा उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने पारंपरिक हथियार। दुश्मन के संचार नेटवर्क को बाधित करना तथा अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना नई युद्ध रणनीति का आधार बन रहा है। ऐसे परिदृश्य में वही राष्ट्र आगे रहेगा, जो साहस और तकनीक के बीच संतुलन स्थापित कर सके। "नेशन फर्स्ट" केवल एक नारा नहीं, बल्कि हर भारतीय सैनिक के जीवन का संकल्प है। यह हर नागरिक के लिए भी मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। सीएम योगी बुधवार को प्रयागराज में "रक्षा त्रिवेणी संगम" की थीम पर नॉर्थ टेक सिम्पोजियम (एनटीएस) 2026 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

आधुनिक युद्ध में कीबोर्ड भी एक प्रभावी हथियार–मुख्यमंत्री ने कहा कि सियाचिन की जमाने वाली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती रेत, घने जंगलों का अंधकार या समुद्र व आकाश की अनंत चुनौतियां, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में तत्पर रहते हैं। उनकी सतर्क निगाहों के कारण ही पूरा देश सुरक्षित और निश्चिंत रह पाता है। आधुनिक युद्ध अब केवल जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के युग में प्रवेश कर चुका है। युद्ध में साइबर, स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे क्षेत्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। कीबोर्ड भी एक प्रभावी हथियार बन चुका है। दुश्मन के पावर ग्रिड, राडार, जीपीएस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करना या अपने नेटवर्क को सुरक्षित व अभेद्य बनाना, नई सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। सेटेलाइट्स के माध्यम से निगरानी, खुफिया जानकारी और नेविगेशन अब युद्ध की 'आंख' और 'दिमाग' बन चुके हैं। अब लड़ाई सिग्नल्स और डेटा के माध्यम से भी लड़ी जा रही है।

DIG अजय साहनी ने SSP ऑफिस का किया औचक निरीक्षण, DCRB से लेकर LIU तक खंगाले रजिस्टर, कमियां मिलने पर दिए सुधार के निर्देश

लोकतंत्र की शान

(बरेली संदीप चंद्रा उत्तर प्रदेश) बरेली कोतवाली क्षेत्र में आज SSP अनुराग आर्य के साथ पहुंचे DIG, समन सेल और LIU ऑफिस की भी ली जानकारी, पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर बरेली रेंज के DIG अजय साहनी ने बुधवार कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित SSP ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ SSP अनुराग आर्य भी मौजूद रहे। DIG ने DCRB, समन सेल और LIU ऑफिस का गहन मुआयना किया और सभी विभागों के रजिस्टरों की बारीकी से जांच की।

रजिस्टरों में मिली खामियों पर DIG ने जताई नाराजगी–निरीक्षण के दौरान DIG अजय साहनी ने रिकॉर्ड मेंटेनेंस और फाइलिंग सिस्टम को चेक किया। कई विभागों में मिली कमियों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। DIG ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड को अपडेट और पारदर्शी रखना जरूरी है, ताकि किसी भी केस में त्वरित कार्रवाई हो सके। SSP अनुराग आर्य ने DIG को विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी दी। DIG ने सभी शाखाओं को समय-सीमा में काम पूरा करने और लंबित मामलों का निस्तारण जल्द करने को कहा।पुलिसिंग को चुस्त-दुरुस्त करने पर फोकस DIG ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही बरतें। उन्होंने कहा कि रजिस्टरों की नियमित जांच और रिपोर्टिंग से ही पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। SSP ऑफिस में हुए इस निरीक्षण को पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि DIG के निर्देशों पर अमल कर सभी विभागों को अपडेट किया जाएगा।

आशिक के साथ फरार हुई पत्नी को अब नहीं रखना चाहता पति कन्हैया

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बता ते चले कि हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला निवासी कन्हैया पुत्र किशनलाल की पत्नी गायत्री उर्फ रानी अपने दो बच्चों को छोड़कर बीती 18 अप्रैल को अपने आशिक सोनू पुत्र घासीराम निवासी शाहपुर कला के साथ फरार हो गई थी जिसकी 20 अप्रैल को कोतवाली में पति द्वारा आरोपी को नाम जद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था, वही पुलिस आरोपी व पीड़ित की पत्नी को तलाश रही है इसी बीच अब पीड़ित पति कन्हैया अपनी पत्नी गायत्री उर्फ रानी को अपने साथ नहीं रखना चाहता वह उसे तलाक चाहता है, वही पीड़ित पति कन्हैया का आरोप है कि पत्नी का आशिक आरोपी सोनू पुत्र घासीराम फोन पर मारने, पीटने की धमकी दे रहा है, वहीं इस संबंध में पीड़ित व पीड़ित के चाचा सीताराम ने बताया कि यदि पीड़ित कन्हैया पुत्र किशन लाल के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार सोनू व उसका पूरा परिवार होगा।

गोदाम से 20 लाख का तांबा उड़ाने वाले गैंग का सीबीगंज पुलिस ने किया पर्दाफाश, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल

लोकतंत्र की शान

(बरेली संदीप चंद्रा उत्तर प्रदेश)बरेली के थाना सुबीगंज क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तांबा चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनमें से दो बदमाश पुलिस की जवाबी कारवाही में पैर में गोली लगने से घायल हो गए जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल को सिविल लाइंस निवासी शिवानी जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट से अज्ञात चोरों ने दीवार के पास सुरंग बनाकर करीब दो टन कॉपर स्क्रैप लगभग लाख कीमत के चोरी कर लिए इस पर थाना सिबीगंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी 6 मई को पुलिस टीम बंडिया नहर के पास चेकिंग कर रही थी तभी सूचना मिली कि चोरी किया गया तांबा बेचने के लिए तीन बदमाश ई रिक्शा से आ रहे हैं पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया लेकिन आरोपी भागने लगे और ई रिक्शा पलट गया खुद को घिरा हुआ देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें दो बदमाश घायल हो गए मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तार आरोपी निजाम और अब्दुल शमी घायल हुए हैं वहीं मोहम्मद खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचे कारतूस नगदी एक ई रिक्शा और चोरी किया गया 65 किलो तांबे का तार बरामद किया है घायल आरोपियों को इलाज के लिए बरेली के थाना सुबीगंज क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तांबा चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनमें से दो बदमाश पुलिस की जवाबी कारवाही में पैर में गोली लगने से घायल हो गए जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल को सिविल लाइंस निवासी शिवानी जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट से अज्ञात चोरों ने दीवार के पास सुरंग बनाकर करीब दो टन कॉपर स्क्रैप लगभग लाख कीमत के चोरी कर लिए इस पर थाना सिबीगंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी 6 मई को पुलिस टीम बंडिया नहर के पास चेकिंग कर रही थी तभी सूचना मिली कि चोरी किया गया तांबा बेचने के लिए तीन बदमाश ई रिक्शा से आ रहे हैं पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया लेकिन आरोपी भागने लगे और ई रिक्शा पलट गया खुद को घिरा हुआ देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की जिसमें दो बदमाश घायल हो गए मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया गिरफ्तार आरोपी निजाम और अब्दुल शमी घायल हुए हैं वहीं मोहम्मद खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचे कारतूस नगदी एक ई रिक्शा और चोरी किया गया 65 किलो तांबे का तार बरामद किया है घायल आरोपियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है पुलिस ने मामले में नया मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कारवाही शुरू कर दी है दिनांक 28426 को वादिनी श्रीमती शिवानी जैन पत्नी पंकज जैन निवासी सिविल लाइन भटनागर कॉलोनी थाना कोतवाली बरेली के द्वारा थाना सीबीग पर सूचना दी गई कि उनकी अज्ञात चोरों द्वारा उनकी फर्म पद्मावती एसोसिएट जो थाना सीबीग क्षेत्र में स्थित है की बाहरी दीवार के पास सुरंग बनाकर बदमाशों द्वारा गोदाम से दो टन करीब कॉपर स्क्रैप चोरी कर लिया गया इस सूचना पर थाना सीबीगंज बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 170 ब 26 धारा 305 ए 331 वन बीएनएस पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों को की तलाश की जा रही थी इसी क्रम में आज दिनांक 65 2026 को प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज पुलिस टीम के साथ झुमका तराहे से बिलवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बंडिया नहर के पास गस्त कर रहे थे अह चेक उसी समय इनको सूचना मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन बदमाश ई रिक्शा से बिलवा पुल से झुमका तराहे की तरफ आ रहे हैं जिनके पास पद्मावती एसोसिएट फर्म से चोरी किया गया कॉपर स्कैप है इस सूचना पर पुलिस के द्वारा प्रभावी ढंग से घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की गई तथा ई रिक्शा के नजदीक आने पर इनको ई रिक्शा को रोकने का प्रयास किया गया तो ई रिक्शा चालक द्वारा तेजी से ई रिक्शा को मोड़कर कच्चे रास्ते पर भगाया गया जिससे ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया इसके पश्चात बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गईजिससे पुलिस टीम बाल-बाल बची तथा पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं घायल बदमाशों के कब्जे से एक अद एक एक अद तमंचा कार एक एक अद खोखा कारतूस व तीन अद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है घायल बदमाश का नाम पहले का निजाम पुत्र निजाकत निवासी महेशपुर दूसरा अब्दुल शमी पुत्र अब्दुल हफीज निवासी महेशपुर तीसरा बदमाश अब्दुल खालिद पुत्र बाबू बख्श निवासी महेशपुर है इसके कब्जे से 2350 नगद बरामद किया गया है निजाम के पास से 00 नगद और अब्दुल शमी के पास से 850 नगद बरामद किया गया है ई रिक्शा से 65 किलो कॉपर का स्क्रैप जो पद्मावती एसोसिएट फर्म से चोरी किया गया था बरामद किया गया है सभी तीनों दोनों बदमाशों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया और इस संबंध में आवश्यक विधिक कारवाई थाना सीबीग पुलिस के द्वारा की जा रही है

संक्षिप्त समाचार

सहरसा में 9 मई को यातायात चालान निपटान हेतु लोक अदालत का आयोजन

लोकतंत्र की शान : सहरसा | मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत दिनांक 9 मई 2026 को जिला परिवहन कार्यालय, सहरसा में यातायात चालान से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में 31 दिसंबर 2025 तक के वाहन यातायात से जुड़े लंबित चालानों का निष्पादन किया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा आमजनों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परिसर में हेल्प डेस्क, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, बैठने के लिए टेंट-कुर्सी तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 के अंतर्गत शमन के रूप में निर्गत चालानों में से वे चालान, जो 31 मार्च 2026 तक 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं (अर्थात 31 दिसंबर 2025 तक के), उन्हें वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस लोक अदालत में निर्धारित सूची के अनुसार चालान राशि में आंशिक छूट भी दी जाएगी, हालांकि कुछ मामलों में किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे आज से ही जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर अपने 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित चालानों का निपटारा कर निर्धारित छूट का लाभ उठा सकते हैं।

वैशाली के जुड़ावनपुर में विवाहिता की मौत, मां बोली-पति,सास और ननद ने मारा, घटनास्थल सील

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के जुड़ावनपुर में एक 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के मायके वालों ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान पूजा कुमारी (20) के रूप में हुई है। वह बिदुपुर के कंचनपुर निवासी शंकर साह की बेटी थीं। पूजा का विवाह लगभग 11 महीने पहले जुड़ावनपुर निवासी स्वर्गीय हरिचंद्र साह के बेटे अजीत कुमार से हुआ था। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि पूजा की सास और ननद ने उसकी हत्या की है। मृतका के पति अजीत कुमार केरल में मजदूरी करते हैं और घटना के समय वहीं थे। घटना की सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया है। FSL की टीम ने घटनास्थल से आवश्यक नमूने एकत्र कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि ससुराल के लोग, खासकर पति की मौसी, पूजा को प्रताड़ित करती थीं। उनका कहना है कि पूजा अपनी सास की सेवा नहीं करती थी, जिसके कारण सास और बहू के बीच विवाद होता रहता था। मां के अनुसार, हत्या के बाद शव को घर से ले जाकर गंगा नदी में ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान मायके वाले घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी शव को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर भाग गए हैं। बिदुपुर थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि परिजनों से लिखित आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया है।

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता प्रेग्नेंट, वीडियो वायरल की धमकी देकर ब्लैकमेल, एफआईआर के बाद भी पुलिस सुस्त

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के लालगंज में एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती हो गई है। घटना के महीनों बाद भी पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है, जबकि पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। पीड़िता ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पड़ोस की एक सहेली पूजा कुमारी जो रिश्ते में बुआ लगती थी, उसे अपने घर ले गई। सहेली ने बहाना बनाया कि वह घर में अकेली है और उसे डर लगता है, इसलिए पीड़िता रात में उसके साथ सोए। पीड़िता के मना करने पर सहेली ने उसके परिजनों को भी अपनी परेशानी बताकर भरोसे में लिया। पड़ोसी लड़की के घर पहुंचने के बाद, उसने बगल के दो लड़कों साहिल और वरुण कुमार को भी वहां बुला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर नाबालिग को दूध और पानी में कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर सुला दिया। पीड़िता के अनुसार, अगली सुबह उठने पर उसे अपने कपड़े बिखरे मिले, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके साथ गलत हुआ है। इस घटना के बाद, पड़ोसी लड़की और दोनों लड़कों ने मिलकर नाबालिग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वे उसे बार-बार संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थे और ऐसा न करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे। डर के मारे पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया। हाल ही में, करीब एक-दो महीने पहले, पीड़िता के शरीर में कुछ बदलाव आने पर वह अपनी मां के साथ सदर अस्पताल पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर उसने पूरी घटना बताई। सामाजिक स्तर पर न्याय न मिलने के बाद, पीड़ित परिवार ने लालगंज थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। हालांकि, प्राथमिकी के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। अभी तक दोनों आरोपी फरार चल रहा है।

60 लाख में तय होती थी नीट की एक सीट, मुजफ्फरपुर के 3 बदमाश समेत 4 अरेस्ट

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। NEET परीक्षा में सॉल्वर बैठाकर पास कराने वाले संगठित गिरोह के बदमाश अरेस्ट हुए है। इस मामले में पहले गिरफ्तार सरगनाओं की निशानदेही पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में छापेमारी कर चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस कांड में कुल 7 बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। 3 मई की रात पावापुरी थाना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान दो लग्जरी गाड़ियों (स्कॉर्पियो-N और ब्रेजा) से तीन सरगनाओं को गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य आरोपी विम्स मेडिकल कॉलेज का MBBS छात्र अवधेश कुमार है। उसके मोबाइल की जांच में कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि गिरोह NEET परीक्षा पास कराने के लिए एक अभ्यर्थी से 50 से 60 लाख रुपए तक वसूलता था। इसमें से 1.5 से 2 लाख रुपए एडवांस के तौर पर पहले ही ले लिए जाते थे। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर बैठाने की तैयारी की जाती थी। सरगनाओं की निशानदेही पर पुलिस ने औरंगाबाद, जमुई और मुजफ्फरपुर समेत अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी परीक्षा में सॉल्वर बैठाने वाले थे, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के कारण योजना पूरी नहीं हो सकी। पुलिस ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें सीतामढ़ी के साउथ गेट, सदर अस्पताल क्षेत्र निवासी डॉ. नरेश कुमार दास के बेटे हर्षराज के साथ मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी मनोज कुमार (पिता- सुरेंद्र प्रसाद यादव) शामिल है। इसके अलावा बोचहां निवासी गौरव कुमार (पिता- अभिषेक रंजन) और हथौरी थाना क्षेत्र के बलुआ निवासी सुभाष कुमार (पिता- कुशेश्वर साह) अरेस्ट हुआ है। चारों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि परीक्षा से पहले ही 1.5 से 2 लाख रुपए एडवांस सरगना को दिए जाते थे और पास कराने के लिए 50-60 लाख रुपए तक की डील फाइनल होती थी। इस गिरोह में उज्ज्वल राज उर्फ राजा बाबू, अवधेश कुमार और अमन कुमार सिंह मुख्य भूमिका में थे। गिरफ्तार आरोपियों को 5 मई को कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े और भी लोगों का खुलासा हो सकता है।

पटना में पिस्टल सटाकर दंपती से लूटपाट, 2 आरोपी गिरफ्तार

बदमाशों से सोने की चेन बरामद, तीसरा आरोपी फरार, सीसीटीवी से खुला राज

लोकतंत्र की शान, पटना

राजधानी में दिनदहाड़े दंपति से पिस्टल के बल पर लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वारदात को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदित्य राज और पप्पू के रूप में हुई है। इनके पास से लूटी गई सोने की चेन के कुछ टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। पटना पुलिस जल्द ही इस मामले का पूरा खुलासा कर सकती है। सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया, सबसे पहले राजीव नगर के रहने वाले पप्पू नाम के व्यक्ति को आईडेंटिफाई किया गया। इसके खिलाफ पहले से भी छपरा और पटना में लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। इस घटना में दानापुर के रहने वाले राजेश पाल ने लाइनर की भूमिका निभाई थी। संतोष दत्तू को ठाकुरबारी और आदित्य राज को दीघा से अरेस्ट किया गया है। एक ने सोना खरीदा था और दूसरे ने गला कर उसे आगे खपाने की तैयारी में था। इनके पास से लूटी गई चेन 40 ग्राम रिकवरी

कर ली गई है। पप्पू और राजेश पाल का पूर्व के 4-5 आपराधिक घटनाओं में अपराधिक इतिहास पाया गया है। इस घटना में शामिल फरार चल रहे अन्य दूसरे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

बंदूक के नोंक पर लूटपाटः घटना शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के समनपुरा गली में हुई थी। जानकारी के अनुसार, दंपति बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया और पिस्टल सटाकर सोने की चेन छीन ली। जब दंपति ने विरोध किया, तो बदमाशों ने पिस्टल तान दिया और उनके साथ मारपीट की। फिर हथियार लहराकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित दामोदरम केपी और अलया फतीमा पटना के हाई कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ हैं। सुबह के वक्त पत्नी के साथ कॉलेज आ रहे थे। इसी बीच कॉलेज से चंद कदम की दूरी पर घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया।

CCTV में कैद हुई पूरी घटना : यह पूरी वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना के समय सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन बदमाशों के हाथ में पिस्टल देखकर कोई भी बीच-बचाव के लिए आगे नहीं आया।

पुलिस जांच में जुटीः मामले में पटना सेंट्रल एसपी दीक्षा ने बताया कि, 'सुबह के समय समनपुरा इलाके में छिनतई की घटना सामने आई है। पीड़ित दंपति से बदमाशों ने लूटपाट की है। इस संबंध में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

ज्ञान भारत मिशन के तहत सहरसा में पाण्डुलिपि सर्वेक्षण तेज, 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ सामग्री मिली

लोकतंत्र की शान

सहरसा | मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः भारत सरकार के ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत जिला पदाधिकारी श्री दीपेश कुमार के निर्देशन में जिले में व्यापक स्तर पर पाण्डुलिपि सर्वेक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सर्वेक्षण टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी स्नेहा झा एवं उग्रतारा भारती-मंडन संस्कृत महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य डॉ. आनन्द दत्त झा ने महिषी निवासी पं. चन्द्रशेखर चौधरी के सहयोग से पड़री ग्राम निवासी पं. विभाकर झा के आवास पर लगभग 200 वर्ष पुरानी पाण्डुलिपियों का विधिवत अवलोकन किया। इन पाण्डुलिपियों में ज्योतिष, वेद एवं कर्मकाण्ड जैसे विषयों से संबंधित संस्कृत भाषा की दुर्लभ सामग्री मिथिलाक्षर एवं देवनागरी लिपि में सुरक्षित पाई गई। यह सामग्री क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि यदि उनके पास 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी कोई भी पाण्डुलिपि उपलब्ध हो, तो उसका सर्वेक्षण अवश्य कराएं। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी ने बताया कि सर्वेक्षण कराने वाले व्यक्तियों को जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी ने आपूर्ति व गैस वितरण की समीक्षा की, कंपनियों को कड़े निर्देश

लोकतंत्र की शान

सहरसा | मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आज जिले में पेट्रोलियम उत्पादों, घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस की उपलब्धता तथा सिटी गैस नेटवर्क (PNG) की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं और विभिन्न तेल कंपनियों के प्रदर्शन पर विस्तृत चर्चा हुई।

सिटी गैस (PNG) कार्य में लापरवाही पर फटकारः समीक्षा के दौरान इंडियन ऑयल (IOCL) के क्षेत्र प्रबंधक को सिटी गैस और PNG पाइपलाइन बिछाने के कार्य में धीमी प्रगति और लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक

सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीजल की कृत्रिम किल्लत पर सख्त रुखः बैठक में यह बात सामने आई कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) द्वारा जिले में डीजल आपूर्ति को लेकर कृत्रिम संकट उत्पन्न किया गया है। इस पर जिला पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी के प्रतिनिधियों को कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। चेतावनी दी गई कि यदि आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वाणिज्यिक सिलेंडरों की कमी पर चिंताः वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की बाजार में बढ़ती कमी पर भी चिंता व्यक्त की गई। स्थानीय व्यवसायियों और होटल संचालकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए वितरकों को स्टॉक बढ़ाने और मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत गैस और एचपी गैस के विभिन्न वितरकों के पास लंबित बुकिंग (बैकलॉग) की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कुछ स्थानों पर 4 से 8 दिनों तक का बैकलॉग पाया गया, जिसे जल्द से जल्द समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

सहरसा पुलिस को बड़ी सफलताः 25,000 का इनामी अपराधी गौरव झा उर्फ गौरव मिश्रा गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

सहरसा |मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसाः पुलिस अधीक्षक, सहरसा के निर्देशानुसार जिले में अपराध नियंत्रण, फरार/वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अवैध हथियारों की बरामदगी को लेकर लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहरसा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 के इनामी फरार अपराधी गौरव झा उर्फ गौरव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को दिनांक 06.05.2026 को रात्रि लगभग 02:00 बजे सोनवर्षाराज थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 25,000 का इनामी अपराधी गौरव झा उर्फ गौरव मिश्रा बलवाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–बधवा में छिपकर रह रहा है तथा लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में अंचल निरीक्षक, सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षाराज थाना, सौरबाजार थाना, बलवाहाट थाना एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम शामिल रही। सभी के समन्वित प्रयास से सुनियोजित ढंग से छापेमारी एवं घेराबंदी की गई।

अनंत सिंह पर एफआईआर, हथियारों संग समर्थकों ने किया था डांस

लोकतंत्र की शान, पटना

गोपालगंज पुलिस ने मोकामा से JDU विधायक और बाहुबली अनंत सिंह पर FIR दर्ज की है। 3 दिन पहले अनंत सिंह गोपालगंज के मीरगंज में एक जनेऊ कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उनके समर्थकों ने खुलेआम हथियार लहराए थे। इसी कार्यक्रम में अश्लील डांस भी हुआ था। अनंत सिंह डांस पर तालियां बजाते दिखाई दिए थे। हथियार लहराने और डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था। इस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने 9 नामजद समेत कई लोगों पर केस दर्ज किया है।

गोपालगंज में मामले को लेकर अनंत सिंह ने कहा, "हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया और न ही कोई गलत काम किया। जब वह वहां पहुंचे, उस समय कोई व्यक्ति राइफल लेकर नाच-गा रहा था, उससे उनका कोई लेना-देना

जनेऊ में मुजरा देख रहे थे जेडीयू विधायक, बोले- मैंने कोई गलत काम नहीं किया

नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह का कानून नहीं तोड़ा।" उन्होंने कहा, "अगर कहीं जाने को लेकर कोई नियम है, तो यह स्थानीय SP की जिम्मेदारी होती है कि वह स्पष्ट आदेश जारी करे। यदि SP यह निर्देश दें कि उन्हें वहां नहीं जाना है, तो वह बिल्कुल नहीं जाएंगे।

पटना में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप

- रेलवे स्टेशन से उठाया, 2 दिन तक दरिंदगी करते रहे, हेवी ब्लीडिंग होने पर छोड़कर भागे

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना में चलती कार में एक 15 साल की लड़की से गैंगरेप हुआ है। 1 मई को अपराधियों ने लड़की को पटना जंक्शन से उठाया था। इसके बाद अलग-अलग जगहों पर 2 दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया गया। ज्यादा ब्लीडिंग होने पर अपराधी उसे दानापुर जंक्शन के पास छोड़कर भाग गए। लड़की का PMCH में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात बेऊर थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद की है।

अपराधियों ने चलती कार में गैंगरेप कियाः लड़की मोतिहारी की रहने वाली है। वो परिवार के साथ विजयवाड़ा में रहती है। 1 मई को वो विजयवाड़ा से पटना जंक्शन पहुंची थी। वह 28 अप्रैल को वहां से अकेले ट्रेन से चली थी। ट्रेन से उतरने के बाद उसका मोबाइल चोरी हो गया। वो स्टेशन पर बैठकर रो रही थी। इसी बीच एक युवक उसे ऑटो से गांधी मैदान ले गया। फिर कार में पटना घुमाते हुए गैंगरेप किया। शाम को उसे सरिस्ताबाद ले गए। वहां तीनों युवकों ने उसे बंधक बनाकर रातभर सामूहिक दुष्कर्म किया। 2 मई को भी कार में घुमाते हुए दुष्कर्म किया गया। शाम को मुख्य आरोपी विकास उसे दानापुर स्टेशन के पास छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद विकास दोबारा

स्टेशन पहुंचा यह देखने कि वह गई या नहीं। वहां वह नाबालिग को धमकाने लगा। यात्रियों ने विवाद देखकर दानापुर रेल पुलिस को सूचना दी, जिसने विकास को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों ने पूरी साजिश की फिर पीड़िता से बेरहमी कीः विकास ने पूरी साजिश के तहत अपने दोस्त अरविंद को कार लेकर गांधी मैदान बुलाया था। दोनों ने नाबालिग का मुंह बंद कर उसे जान से मारने की धमकी दी। शाम होते ही वे उसे सरिस्ताबाद के एक निर्माणाधीन मकान में ले गए। वहां निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन मजदूर जा चुके थे। मकान के एक कमरे में एक चौकी और बड़ा फ्रीजर रखा था। पहले तीनों ने उसे वहीं खाना खिलाया। इसके बाद रातभर में दो-तीन बार जबरन गैंगरेप किया। इस खौफनाक दरिंदगी में पीड़िता के शरीर से काफी ब्लीडिंग होने लगी। वह दर्द से तड़पती और रोती रही, लेकिन दरिंदों को जरा भी तरस नहीं आया। उसे उसी हालत में स्टेशन छोड़ आए।

लोगों की सतर्कता से पकड़े गए दो आरोपीः 2 मई की शाम विकास ने नाबालिग को कार से दानापुर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया। वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गई। विकास यह देखने के लिए स्टेशन के अंदर गया कि वह ट्रेन में बैठी या नहीं। वहां वह पीड़िता से दोबारा साथ चलने की जिद करने लगा। नाबालिग ने कड़ा विरोध किया। दोनों के बीच बहस देख रहे रेल यात्रियों ने दानापुर जीआरपी को सूचना दे दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर विकास को दबोच लिया। विकास की निशानदेही पर ही पवन की गिरफ्तारी हो सकी। रेल SP अनंत कुमार राय ने बताया कि दानापुर GRP में गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। पुलिस ने पीड़िता को PMCH में भर्ती कराया, जहां उसका फर्द बयान दर्ज किया गया और इलाज चल रहा है।

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में फैसला टला, 22 मई को फैसला सुनाएगी कोर्ट

लोकतंत्र की शान, पटना

IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला टल गया है। कोर्ट ये फैसला अब 22 मई को फैसला सुनाएगी। अदालत ने पहले ही आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ED ने लालू यादव परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो सकता है। बताया जा रहा कि लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा कि उनके पास मामले से जुड़े पर्याप्त और पुख्ता सबूत मौजूद हैं। CBI का

दावा है कि जांच के दौरान कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं, जो आरोपों को मजबूत करते हैं। यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान IRCTC के तहत आने वाले रांची और पुरी स्थित दो होटलों के टेंडर में अनियमितताएं की गईं। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन होटलों और उनसे जुड़ी जमीनों को निजी कंपनियों को नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टे पर दिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था और इससे कुछ निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

सुपौल अवर निबंधक अमरेन्द्र कुमार पर ईओयू का एक्शन, पटना समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी

लोकतंत्र की शान, पटना

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बुधवार सुबह सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेन्द्र कुमार के पटना सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। अमरेन्द्र कुमार पर आय से लगभग 65.08 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। ईओयू सूत्रों के मुताबिक, अमरेन्द्र कुमार के खिलाफ सत्यापन के बाद आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-06/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अमरेन्द्र कुमार ने अपनी वैध आय से लगभग 1 करोड़ 10 लाख 64 हजार रुपए अधिक संपत्ति अर्जित की है।

पटना सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी जारीः माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद, ईओयू ने बुधवार सुबह एक साथ चार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी कर

रहे हैं। जिन स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, उनमें पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित राज अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या- 305, सारण (छपरा) स्थित पैतृक आवास, सुपौल स्थित उनका कार्यालय और किराये का घर भी शामिल है।

EOU के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह जानकारी मिली है कि अमरेंद्र कुमार ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा इलाके में एक बड़ा जमीन खरीद रखा है। यह जमीन दार्जिलिंग व्यू सोसाइटी में स्थित है, जहां उन्होंने करीब 30 से 35 कट्ठा भूमि अपने नाम पर ली है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब पांच करोड़ रुपये बताई जा रही है। EOU को मिले दस्तावेजों और प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस जमीन की घेराबंदी पर ही लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। खास बात यह है कि जमीन को साधारण तरीके से नहीं, बल्कि किलानुमा संरचना बनाकर सुरक्षित किया गया है, जिससे इसकी भव्यता और निवेश की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जांच एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि इतनी बड़ी राशि का निवेश किन स्रोतों से किया गया और क्या इसमें अवैध आय का उपयोग हुआ है। साथ ही जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन के विवरण को भी खंगाला जा रहा है। EOU के मुताबिक, छापेमारी के दौरान मिले इस साक्ष्य से जांच को नई दिशा मिली है। अधिकारियों का दावा हैं कि छापेमारी के बाद और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

राजनीति घराने में कल्याण परिवार का विवाद सड़कों पर उतरा

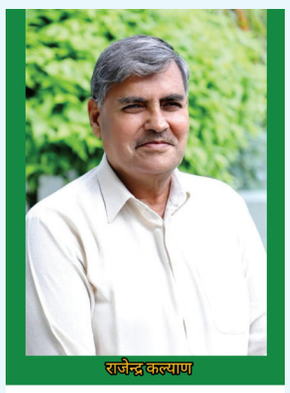
राजेन्द्र कल्याण

लोकतंत्र की शान : राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट : अगर 400 एकड़ यूनिवर्सिटी की आवाज राजेंद्र कल्याण सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर उठाये तो हरविंदर कल्याण क्यों परेशान और उस परेशानी वह गुस्से में अपने अलसेशियन संजय खेंची रिश्तेदार भाई राइट हैंड को शह देकर राजेंद्र कल्याण को गालियां अपशब्द ब*** मेंटल जैसी गालियां दी गई यह किसके इशारे पर हुआ बिना अलसेशियन राज्य मंत्री की हिम्मत नहीं कि वह पूर्व मंत्री मुल्तान सिंह व पूर्व चेयरमैन कुलदीप जाट शेखपुरा अपने चेले दीपक शर्मा से यह लिखवाएं की सरकार के सारे पेड़ बेचकर खा गया था,, स्पीकर हरविंदर कल्याण जी तीन दिन हो गए अगर यह सहमति नहीं होती तो आप चुप क्यों रहे क्या कल्याण फार्म पर जो व्यक्ति किसी काम से आते हैं अलसेशियन संजय खेंची उनसे फोन लेकर गालियां देने का काम करता है पूर्व विधायक रमेश राणा रिश्तेदार दाहिना हाथ लाढडा भी यही काम करता था और उसी के व्यवहार को रमेश राणा ने भुगता, राजेंद्र कल्याण का कहना है कि अपने अलसेशियन से खूब गालियां दिलवा लेकिन राजेंद्र कल्याण लोगों की भलाई के लिए एवं उनके मुद्दे उठाने में पीछे नहीं हटेंगे ना ही गालियों से डरेंगे राजेंद्र कल्याण ने कहा गालियां तो मेरे लिए सुहानी बन गई है जनता को तुम्हारे चरित्र एवं फायदे की बजायें नुकसान ही होगा कहीं ऐसा ना हो स्पीकरी ले ले उन्होंने कहा भाई को चुनाव होते ही चुनाव आयोग का कामगार बनवा दिया और अगर राजेंद्र कल्याण आवाज उठायें तो गालियां देकर डराओ जो डरने वाला नहीं है

यमुनानगरः ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

लोकतंत्र की शान : यमुनानगर। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे स्टेशन के निकट एक रेल की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मंगलवार देर रात स्टेशन मास्टर की ओर से सूचना दी गई कि नहर के पास बने रेलवे पुल के समीप पटरी पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही जीआरपी टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आया था, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव की स्थिति से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मृतक के शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, जिससे पहचान करना कठिन हो रहा है। पुलिस ने मौके से शव को एकत्रित कर सिविल अस्पताल यमुनानगर की मोर्चरी में रखवा दिया है। तलाशी के दौरान मृतक के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। अनुमान है कि उसकी उम्र करीब 45 वर्ष के आसपास हो सकती है। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है और लापता व्यक्तियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।

हिसार : सीएमओ ने दिया मांगों के समाधान का आश्वासन, आंदोलन स्थगित

लोकतंत्र की शान : हिसार। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की स्वास्थ्य विभाग शाखा ने कर्मचारियों की मांगों बारे बुधवार को लगातार तीसरे दिन सीएमओ कार्यालय पर गेट मीटिंग कर दो घंटे रोष प्रदर्शन किया। गेट मीटिंग की अध्यक्षता शाखा प्रधान अजमेर ने की जबकि जिला सचिव दीपक खत्री ने संचालन किया। गेट मीटिंग के दौरान कर्मचारियों के रोष को देखते हुए सीएमओ ने यूनियन प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। इस पर यूनियन प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए सीएमओ कार्यालय पहुंचा। शाखा प्रधान अजमेर ने बताया कि बातचीत में सीएमओ ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर मांगों को समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएमओ के आश्वासन के बाद यूनियन ने बैठक कर आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में शाखा प्रधान अजमेर, जिला सचिव दीपक खत्री, सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान राजेश बागड़ी, वरिष्ठ उपप्रधान अशोक कुमार, जिला वरिष्ठ उपप्रधान बिशन, हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन के राज्य उपप्रधान रामफल शिकारपुर, जिला प्रधान छबील दास मोलिया, उपप्रधान ममता देवी, स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी संयोजक नूर मोहम्मद व विनोद दलाल शामिल रहे। गेट मीटिंग को हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी युनियन सिंचाई विभाग शाखा प्रधान अशोक श्योकंद, सचिव राजेश दलाल, कैशियर अनिल, वरिष्ठ उपप्रधान ईश्वर सोढ़ी, उपप्रधान सुरेन्द्र भ्याण, वेदप्रकाश, विक्रम, पवन कुमार, नीरज कुमार, सोमवीर, पंकज, किसान नेता सुरेन्द्र मान, दमकल विभाग के जिला प्रधान राजेश महला व एमपीएचई एसोसिएशन से अनूप ढुल आदि ने भी संबोधित किया।

गुरुग्रामः पति ने पत्नी की हत्या कर शव सडक़ किनारे फेंका

लोकतंत्र की शान : गुरुग्राम। एक व्यक्ति ने बुधवार को अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर से करीब 100 मीटर दूर सडक़ किनारे फेंक दिया। महिला की पहचान उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी रेखा के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। जानकारी के अनुसार रेखा अपने पति गौरव के साथ मानेसर के पास भांगरौला गांव में रहती थी। रेखा और गौरव की अरेंज मैरिज हुई थी। गौरव मानेसर स्थित एक निजी कंपनी में काम करता है।

रादुविवि में शासन की छात्र हितैषी योजनाओं की उड़ रही धज्जियां

लोकतंत्र की शान

» संबल और मेधावी विद्यार्थियों से शुल्क वसूली पर भड़का छात्र आक्रोश

» कुलसचिव कार्यालय में घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ता; शिक्षण विभागों में अराजकता एवं अव्यवस्था के लगाए गंभीर आरोप

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में आज उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ पांच सूत्रीय मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों एवं कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर छात्र विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कुलगुरु एवं कुलसचिव के अनुपस्थित रहने से छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। लगभग आधे घंटे तक प्रदर्शन करने के बावजूद जब कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी छात्रों से चर्चा करने नहीं पहुंचा, तब आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के भीतर प्रवेश करते हुए कुलसचिव कार्यालय का घेराव कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया किंतु प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता कार्यालय कक्ष के भीतर पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी।लगभग एक घंटे तक कुलसचिव कार्यालय के भीतर छात्रों द्वारा लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन किया जाता रहा। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, जिसके बाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक मौके पर पहुंचे और छात्रों से चर्चा कर उनका ज्ञापन प्राप्त किया। इस दौरान छात्रों ने कुलगुरु पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि कुलगुरु केवल कुछ खास लोगों से ही मुलाकात करते हैं तथा सामान्य छात्रों की समस्याओं और छात्र हितों से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह संवेदनहीन हो चुका है और छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई नेता अनुराग शुक्ला ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शासन की छात्र हितैषी योजनाओं का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन की संबल एवं मेधावी विद्यार्थी योजना के पात्र छात्रों से नियमों के विपरीत परीक्षा एवं अन्य शुल्क वसूले जा रहे हैं, जबकि मध्यप्रदेश शासन की प्रवेश मार्गदर्शिका एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07/07/2025 के अनुसार ऐसे छात्रों से केवल कॉशन मनी लिए जाने का ही प्रावधान है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का शोषण कर रहा है।कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय ग्रंथालय में प्लेजियरिज्म जांच के नाम पर कथित अनियमित वसूली, शोधार्थियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था के अभाव तथा विश्वविद्यालय में UGC के अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम संबंधी विनियमों के पालन न होने का मुद्दा भी उठाया। इसके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स के साथ हो रही उपेक्षा पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि अप्रैल 2026 में मध्यप्रदेश शासन एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीसी विस्तार और कैडेट्स को प्रोत्साहन देने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, किंतु विश्वविद्यालय स्तर पर न तो कोई समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और न ही कोई प्रभावी समन्वय व्यवस्था विकसित की गई है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के अनेक अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते, जिसके कारण विद्यार्थियों को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए घंटों इधर-उधर भटकना पड़ता है। कई बार छात्र दस्तावेजों, परीक्षा संबंधी कार्यों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए संबंधित कर्मचारियों को खोजते रहते हैं, लेकिन कार्यालयों में उनकी अनुपस्थिति बनी रहती है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समन्वय समिति की 101वीं बैठक में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया था, किंतु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के अनुराग शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव देवकी पटेल, प्रदेश सचिव प्रतीक गौतम, सैफ मंसूरी, शफी खान, अदनान अंसारी, अंकित शुक्ला, राजीव श्रीवास्तव, सोनू मेशराम, निखिल वंशकार, तीरथ श्रीवास, आलोक शर्मा, अनमोल प्रजापति, आर्यन चौधरी, युग ठाकुर सहित बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

आंधी तूफान ने छीना गरीब के सिर का छप्पर

» रामपुर नैकिन तहसील के आमडांड गांव का मामला

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

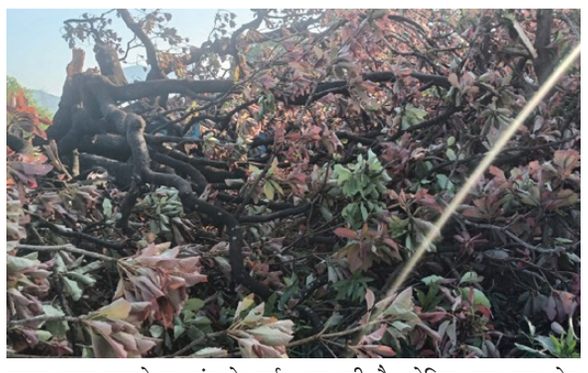

सीधी। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई गरीबों का आशियाना तक छिन गया। वहीं मंगलवार को जिले भर में तेज तूफान एवं बारिश के साथ कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसा ही मामला जिले के थाना रामपुर नैकिन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमडांड 44 में तेज तूफान के चलते एक गरीब परिवार का पूरा आशियाना ही धराशाई हो गया। आमडांड 44 निवासी पीड़ित रामचंद्र द्विवेदी ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ अपने घर के अंदर बैठा था। तभी तेज तूफान से अचानक घर के बगल में महुआ का बड़ा पेंड अचानक मेरे घर में गिर गया जिससे मेरा पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। मेरे बच्चों के साथ पूरे परिवार में उस समय दहशत का माहौल छा गया। हल्ला गुहार मचाने पर गांव के कई लोगों ने आकर हम सबको घर से बाहर निकाला। साथ ही कुछ पालतू मवेशी भी महुआ के पेंड़ की चपेट में आकर फंसे हुए थे जिनको भी ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। हाल यह है कि अब हम लोगों को रहने के लिए दूसरों के घरों का सहारा लेना पड़ रहा है। घर में रखा मेरा अनाज समेत घर की अन्य सामग्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों के सहयोग से मेरे पूरे परिवार को रहने एवं खाने की सुविधा की समुचित व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जब तक मेरा पुनः मकान का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं कितने दिन दूसरों के सहारे रहूंगा। मेरे पास जीवकोपार्जन के लिए केवल एक ही माध्यम है जब मैं मजदूरी करके आता हूं तभी मेरे पूरे परिवार का भरण-पोषण होता है, ऐसे में कुदरत का कहर मेरे पूरे परिवार को दाने-दाने को मोहताज कर दिया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि मुझ गरीब परिवार को सहायता राशि एवं क्षतिग्रस्त हुए सामग्री की उचित व्यवस्था कराई जाए।

तीन माह में ही ढही लाखों की नाली बारिश ने खोली घटिया निर्माण की पोल

» चुरहट नगर परिषद के निर्माण कार्य पर उठे सवाल, कार्रवाई की मांग तेज

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

चुरहट/सीधी। नगर परिषद चुरहट के बिछी रोड पर हाल ही में निर्मित लाखों रुपये की नाली मंगलवार रात हुई मामूली बारिश भी नहीं झेल सकी और भरभराकर ढह गई। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री और कमजोर कार्य की शिकायतें लगातार की जा रही थीं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बताया गया कि करीब तीन माह पहले बनाई गई नाली पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। इससे नगर परिषद के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों पर ध्यान दिया जाता, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती और जनता के पैसों की बर्बादी रोकी जा सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर परिषद सीएमओ , नगर परिषद उपाध्यक्ष एवं इंजीनियर मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उपाध्यक्ष अजय पांडेय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने इस मामले में संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और जिम्मेदार इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएमओ रामअवतार पटेल ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई लोक अदालत के प्रचार रथ को हरी झंडी

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर सीधी एवं तहसील मुख्यालय चुरहट, मझौली तथा रामपुर नैकिन में दिनांक 09 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्रधान जिला न्यायाधीश दिनकर ने नेशनल लोक अदालत के समुचित प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 06.05.2026 को प्रचार रथ को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ तथा पंप्लेट्स वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जावेगा। इसके साथ ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी दिनकर द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में सभी न्यायाधीशगण के साथ समीक्षा बैठक की। उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री दीपक शर्मा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ बृजेन्द्र सिंह, विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरू, द्वितीय जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी, तृतीय जिला न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राकेश जमरा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार वर्मा, न्यायाधीशगण सोनू जैन, सुश्री सरिता चौधरी, कपिल देव काछी, सुश्री अर्पिता त्रिपाठी, धीरज आर्य, आकर्ष मिश्रा, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, मनबहोर पटेल कार्यालय सहा. 2 विद्युत विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण सहित जिला न्यायालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे ने बताया कि आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण सर्वोत्तम तरीका है जिससे समय एवं धन की क्षति रूकती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। शिवहरे ने कहा कि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रकरण पूरी तरह समाप्त हो जाता है और सभी पक्षकारों की जीत होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालयों के बाहर आपसी समझौता होता है, जिसे वापस न्यायालय में प्रेषित किया जाता है, तदनुसार न्यायालय द्वारा समझौते का निर्णय दिया जाता है।

सैनिकों की समस्याओं के समाधान को जिला प्रशासन की नई पहल, "हेलो सीधी-जय जवान" शुरू

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिला प्रशासन सीधी द्वारा सेवारत सैनिकों के सम्मान, सुविधा और समस्याओं के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता देते हुए हेलो सीधी जय जवान नामक एक अभिनव एवं जनहितैषी पहल की शुरुआत की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य देश की सेवा में समर्पित सैनिकों को एक ऐसी सरल, पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचा सकें और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। उक्त पहल के संबंध में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर सैनिकों के सम्मान एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से यह विशेष पहल प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले सैनिकों एवं उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गुरप कैप्टन सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित सेवा निवृत्त पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे।

शहर विकास को लेकर विधायक रीती पाठक गंभीर, अधिकारियों को दिए समन्वय और गुणवत्ता के निर्देश

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। आमजन को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को समयसीमा में पूर्ण कराने के उद्देश्य से विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सडक़ निर्माण, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, शिक्षा एवं कानून व्यवस्था सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायक श्रीमती पाठक ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए गोपाल दास मंदिर एवं स्टेडियम निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने पर जोर दिया। उन्होंने शासन स्तर पर लंबित कार्यों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका सीधी अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए तथा शहर को सुंदर, स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। यातायात व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने, वार्डों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा नालियों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए गए। विधायक श्रीमती पाठक ने ई-लाइब्रेरी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने, अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर मूलभूत सुविधायुक्त व्यवस्थित कॉलोनियों के विकास की दिशा में कार्य करने तथा समयसीमा से अधिक लंबित कार्यों के ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर में अवैध होर्डिंग हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों एवं उनकी लागत की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विधायक ने रेलवे एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए भूमि अर्जन संबंधी प्रकरणों को समयसीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण एजेंसियों द्वारा खोदे गए गड्ढों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु में किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो।

किशोरी से गैंग रेप,एक आरोपी पकड़ाया,दो फरार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी । घर के छत में रात को सो रही किशोरी का अपहरण कर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात के सामने आने पर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो फरार है। आरोपियों ने इस घिनौनी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़िता अपने घर की छत में सो रही थी और घर में उसकी मां और छोटी बहन सो रही थी। मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना 2 मई की रात 10 बजे की है। भीषण गर्मी के कारण पीड़िता छत में सोई हुई थी। रात के सन्नाटे का फायदा उठाते हुए जितेंद्र यादव उर्फ प्रिंस और सुनील यादव छत पर आये। जितेंद्र पूर्व परिचित होने से किशोरी को जगाकर साथ चलने को कहा। इंकार करने पर दोनों मुंह दबाकर मोटरसाइकिल से ग्राम कोल्हुआ खेत में ले गये। यहां सुनील यादव ने फोन कर अपने साथी ललन साहू को भी बुला लिया। गैंगरेप के बाद ललन साहू ने पत्थर से पीड़िता के सिर पर प्रहार किया जिससे सिर के दाहिने तरफ चोट आई। फिर आरोपियों ने पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ दिया।

मां को सुनाई आपबीती, **पुलिस में मामला दर्ज-** पीड़िता के सिर में चोंट लगने पर मां ने जब पूंछा तो इस खौफनाक मंजर की जानकारी दी। घटना सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देर किए मां और परिजन किशोरी को लेकर 3 मई को कोतवाली थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। मामला पंजीबद्ध कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने विवेचना तेज कर दी है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 140 (4) , 70 (2) , 115 (2) , 351 (3) बीएनएस, 5 जी, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 , 3 (1) (डब्ल्यू) (आई आई) , 3 (2) (व्ही) , 3(2) (व्हीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीवद्ध किया।

इनका कहना है- मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि नाबालिग (विधि विरुद्ध बालक) है। घटना में शामिल दो अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अभिषेक उपाध्याय, थाना प्रभारी कोतवाली

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाईवे डूबा, घरों में पानी

भोपाल/लखनऊ/जयपुर/पटना। उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को भारी बारिश हुई। इससे कांकेर के चारामा में नेशनल हाईवे-30 पर घुटनों तक पानी भर गया। मनेंद्रगढ़ के जनकपुर में बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया। पेंड्रा में आंधी से कई पेड़ टूटकर गिर गए। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश के कारण पूरे यूपी में अधिकतम तापमान 40°C से नीचे आ गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजस्थान में बाड़मेर और फलोदी को छोड़कर बाकी सभी शहरों में तापमान 40°C से नीचे रहा। इधर, बिहार और मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 89.7 MM बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 182% अधिक है। राज्य में 7 मई तक आंधी-बारिश जारी रहेगी। MP के 28 जिलों में बुधवार को तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम के लिहाज से आने वाले दिन काफी उथल-पुथल भरे साबित हो सकते हैं। एक तरफ जहां अरब सागर में मानसून-पूर्व चक्रवाती तूफान के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहत दे रही बारिश और तेज हवाओं के थमने के बाद उत्तर भारत में गर्मी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी है, लेकिन यह स्थिति 10 मई के बाद पूरी तरह बदलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों और ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 10 मई के आसपास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में एक चक्रवाती सिस्टम बन सकता है। इससे बारिश-तूफान संभव है। आमतौर पर अरब सागर में अप्रैल और मई के शुरुआती हफ्तों में तूफानों की दर काफी कम रहती है, इसलिए यदि यह सिस्टम मजबूत होता है तो इसे एक अपवाद माना जाएगा।

हिमाचल में कैंसर मरीजों के मुफ्त इलाज पर संकट, पेमेंट अटकने से हिमकेयर और आयुष्मान योजना फेल

शिमला। हिमाचल प्रदेश में पांच लाख रुपए तक के मुफ्त उपचार वाली हिमकेयर और आयुष्मान योजना का मरीजों को फायदा नहीं मिल रहा है। इन दोनों स्कीमों के कार्डधारकों को दवाइयां ओपन मार्केट से महंगे दाम पर खरीदनी पड़ रही है, जिससे कैंसर मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कैंसर के स्टेट लेवल हॉस्पिटल IGMC शिमला में उपचार करवा रहे मरीजों व उनके तीमारदारों में सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि सरकार के जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयां तो मिल रही है, लेकिन कीमोथैरेपी की महंगी दवाइयां और इंजेक्शन लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को कैंसर का उपचार मुश्किल हो गया है। कई लोग उधार मांग कर उपचार करवा रहे हैं। केंद्र की आयुष्मान और राज्य की हिमकेयर योजना में कागजों में तो 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान है। हकीकत में सरकार द्वारा पेमेंट का भुगतान नहीं होने से मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। अकेले IGMC शिमला 110 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार पर है। इसी तरह, राज्य के अन्य अस्पतालों में यह देनदारी करोड़ों में पहुंच गई है। आर्थिक तंगहाली से जूझ रही राज्य सरकार समय पर हिमकेयर की पेमेंट का भुगतान नहीं कर पा रही। इसकी मार मरीजों पर पड़ रही है। कैंसर के अलावा दूसरी बीमारियों के मरीजों के भी यही हाल है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं निंदनीय : जमात ए इस्लामी हिद

नई दिल्ली। जमात ए इस्लामी हिंद ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ पुडुचेरी और असम में वर्तमान सरकारों को जनादेश मिलने पर संतोष जताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं को निंदनीय बताया है। जमात-ए-इस्लामी के उपाध्यक्ष मलिक मोहतसिन खान और इंजीनियर सलीम अहमद ने नई दिल्ली के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जनादेश प्राप्त किया है और आने वाले दिनों में नई सरकार भी बनने वाली है। भाजपा समर्थकों के जरिए टीएमसी के कार्यालय और उनके नेताओं के घरों एवं दफ्तरों पर किए जा रहे हमले, तोड़फोड़ और सांप्रदायिक नारेबाजी की घटना दिल को झकझोर देने वाली है। उन्होंने बंगाल में एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम काटे जाने और उन्हें मताधिकार से वंचित किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को चुनाव में मतदान से वंचित करना सही कदम नहीं था। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, उसमें गड़बड़ी और हेरा-फेरी की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी तरह का माहौल असम में भी चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई पड़ा, जहां राजनीतिक दलों के नेताओं ने सभाओं में जिन भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया और नफरत फैलाने की कोशिश की, उस पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से मौन धारण कर रखा था। यहां पर भी चुनाव प्रचार के दौरान एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार किया गया।

इसके अलावा जमात-ए-इस्लामी नेताओं ने देश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में ईंधन, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है और इसका असर हमारे देश भारत पर भी पड़ा है। कमर्शियल और छोटे सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने महंगाई को और भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि अब राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, इससे भी हमारे देश में और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी।

शशि शेखर वेम्पति बने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शशि शेखर वेम्पति को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक शशि शेखर वेम्पति तीन साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। यह नियुक्ति प्रसून जोशी के पद छोड़ने के बाद की गई है। प्रसून जोशी को हाल ही में प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया है, जिसके चलते उन्होंने सीबीएफसी प्रमुख का पद छोड़ा। शशि शेखर वेम्पति मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लंबे अनुभव रखते हैं। इससे पहले वे प्रसार भारती के सीईओ भी रह चुके हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को आमतौर पर सेंसर बोर्ड के रूप में जाना जाता है, जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संस्था है। यह चलचित्र अधिनियम 1952 के तहत फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी सामग्री के सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रमाणित करता है। यानि देश में फिल्मों को प्रमाणित करने वाली प्रमुख संस्था है, जो यह तय करती है कि कोई फिल्म किस श्रेणी में रिलीज होगी।

युवाओं को दिखावे से दूर रहकर अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिएः डॉ. भटनागर

नई दिल्ली। संगीतज्ञ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर डॉ. मधुर लता भटनागर ने कहा कि युवा दिखावे से दूर रहकर अपनी जड़ों से जुड़े और ऐसे काम करें जिससे समाज का भी भला हो। डॉ. भटनागर ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) में चल रहे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (डीआईएफएफ) 2026 के दौरान 7 मई को उनकी लघु फिल्म 'म्यूजिक ऑफ नेचर' प्रदर्शित की जाएगी, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी। उनकी यह 8 मिनट की फिल्म मानवीय पात्रों से मुक्त है। इसमें केवल पेड़-पौधे, झरने, पहाड़, बादल और चाँद-सितारों को ही 'कलाकार' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा, "फूल-पौधे झूमते और गाते हैं, झरनों के बहने में भी एक लय है। मैंने इसी प्राकृतिक संगीत को संजोया है ताकि दुनिया भर में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उन्हें रोका जा सके और लोग प्रकृति की महत्ता को समझें।" फिल्म में कोयल और मोर की वास्तविक आवाजों के साथ बांसुरी और अन्य वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया गया है।" साक्षात्कार के दौरान डॉ. भटनागर ने अपने गौरवशाली अतीत को साझा करते हुए बताया कि वह पहली संगीतकार थीं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को संगीतबद्ध किया था।

बंगाल में भाजपा सरकार, बांग्लादेश को नागरिकों की वापसी का डर

बांग्लादेशी मंत्री बोले- उम्मीद है जबरन नहीं भेजा जाएगा, बॉर्डर फोर्स अलर्ट पर

एजेंसी, ढाका

पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को आशंका है कि उसके लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है। अब इसे लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बयान जारी किया है। उन्होंन कहा उम्मीद है कि भारत से लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी 'पुशबैक' की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए। इसी के मद्देनजर बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।

इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भी कहा था कि अगर ऐसे मामले होते हैं, तो बांग्लादेश कार्रवाई करेगा। पुशबैक का मतलब किसी व्यक्ति को जबरन सीमा पार भेज देना। पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दरअसल बंगाल चुनाव के दौरान BJP ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया था उसने बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को शरण दी है। उधर बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी BNP के सूचना सचिव अजीजुल बारी हेलाल ने BJP को जीत की बधाई दी और कहा कि इससे भारत-बांग्लादेश संबंध मजबूत हो सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीस्ता जल बंटवारे समझौते में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि वह इसमें सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने दावा किया कि यह समझौता बांग्लादेश सरकार और मोदी सरकार दोनों ही चाहते थे। हेलाल ने उम्मीद जताई कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी सरकार भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर बनाएगी और तीस्ता समझौते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि भारत के राज्यों में बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की ही लगती है। इसलिए वहां की राजनीति का असर सीधे दोनों के संबंधों पर पड़ता है। वहां सत्ता बदलना दोनों देशों के लिए अच्छा है। इससे दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर भी सुधार हो सकता है। तीस्ता नदी हिमालय के पाहुनरी ग्लेशियर से निकलती है। यह सिक्किम से पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है और बाद में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इस नदी से बांग्लादेश के 2 करोड़ और भारत के 1 करोड़ लोगों का जीवनयापन जुड़ा है। इस लंबी यात्रा के दौरान तीस्ता नदी की 83% यात्रा भारत में और 17% यात्रा बांग्लादेश में होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कई सालों से विवाद है। बांग्लादेश तीस्ता के 50 फीसदी पानी पर अधिकार चाहता है। जबकि भारत खुद 55% पानी चाहता है। जानकारों के मुताबिक अगर तीस्ता नदी जल समझौता होता है तो पश्चिम बंगाल नदी के पानी का मनमुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि ममता बनर्जी इसे टालती रहीं।

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 होगी, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

एजेंसी, नई दिल्ली

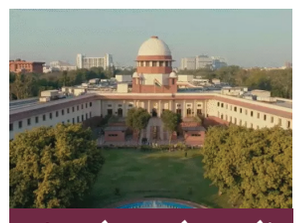

संसद के अगले सत्र में बिल पेश होगा

केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार संसद के अगले सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चीफ जस्टिस समेत 33 जजों की तय संख्या है। सरकार इसमें चार नए जज जोड़ना चाहती है। इसके लिए संसद के अगले सत्र में बिल लाया जाएगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद 1956 के कानून में संशोधन किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए जजों के नाम सरकार को भेजेगा।

2019 में आखिरी बार बढ़ी थी संख्याः इससे पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। वहीं, 2008 में जजों की संख्या 26 से बढ़कर 31 हुई थी। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा सिर्फ 10 जजों की व्यवस्था थी।

सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 पद खालीः फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दो पद खाली हैं। जस्टिस बी.आर. गवई नवंबर 2025 में और जस्टिस राजेश बिंदल अप्रैल 2026 में रिटायर हुए थे। आने वाले महीनों में सुप्रीम कोर्ट में तीन और पद खाली होने वाले हैं। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस पंकज मित्तल जून 2026 में रिटायर होंगे, जबकि जस्टिस संजय करोल अगस्त 2026 में सेवानिवृत्त होंगे। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का जज वही बन सकता है जो भारतीय नागरिक हो। इसके लिए व्यक्ति का कम से कम पांच साल तक हाईकोर्ट में जज रहना या 10 साल तक वकील के तौर पर काम करना जरूरी है। किसी प्रतिष्ठित कानून विशेषज्ञ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है।

हार्मुज से जहाजों को निकालने का अमेरिकी अभियान दो दिनों के भीतर रुका

एजेंसी, वॉशिंगटन

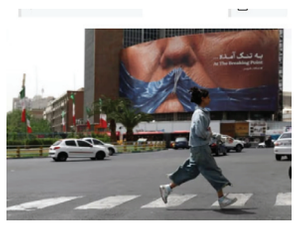

♦ ट्रंप ने कहा-नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने की घोषणा की। यह मिशन हार्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को निकालने के लिए था। ट्रंप ने पाकिस्तान और अन्य देशों से मिले अनुरोधों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। हालांकि, ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज जलडमरूमध्य में फंसे व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की है। लेकिन ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी पहले की तरह जारी रहेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा है कि "पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर और ईरान के खिलाफ चलाए गए अभियान में हमारी सेना को मिली ज़बरदस्त सफलता को देखते हुए—साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई है—हमने आपसी सहमति से यह तय किया है कि, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' (होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही) को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। हालांकि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी।

विजय की शपथ टल सकती है, सरकार बनाने के लिए 118 विधायक जरूरी

एजेंसी, चेन्नई

❐ टीवीके के पास 113, बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार की शपथ

तमिलनाडु में 7 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है। TVK चीफ विजय ने बुधवार को लोकभवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक, विजय ने 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। समर्थन पत्र में TVK 107 और कांग्रेस के 5 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। ANI सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने 118 विधायकों के समर्थन के पत्र की मांग की। इस पर विजय ने समर्थन के लिए समय मांगा।

234 सदस्यीय विधानसभा में TVK की 108 सीटें हैं, लेकिन विजय दो सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर यह 107 रह जाएंगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए TVK को 11 और विधायक चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला है। उधर, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 मई को विधायक दल की बैठक होगी।

TVK को बहुमत के लिए 11 विधायकों की जरूरतः विजय लेफ्ट और वीसीके जैसे छोटे दलों के भी संपर्क में हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर AIADMK से भी समर्थन लिया जा सकता है। हालांकि, AIADMK में 20 विधायकों में टूट की खबर भी आ रही है। कौन-कौन सी पार्टी उन्हें समर्थन देंगी यह साफ नहीं है। TVK ने बुधवार को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के चेंगलपट्टू स्थित फोर पॉइंट्स नाम के रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है।

बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, अब तक 4 की मौतः बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से हिंसा शुरू हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की हत्या हुई। इनमें भाजपा और TMC के 2-2 कार्यकर्ता हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने TMC के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

♦ अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा-जुर्माना, जन-गण-मन से पहले गाया जाएगा

केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी, जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज,संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा।

कानून में बदलाव और सजा का प्रावधानः सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद यही नियम वंदे मातरम पर भी लागू होंगे।

सरकार ने जारी की गाइड लाइनः केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी की। गाइड लाइन के अनुसार, वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक वर्जन, जिसमें छह श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए। इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं।

पहले 'राष्ट्रगीत' गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान'ः अगर किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' और 'राष्ट्रगान' दोनों होने हैं, तो पहले 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगीत) गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान'।दिशा-निर्देशों में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों प्रदर्शनों के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहें।

वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रहः गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेज और महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है।इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स और आम जनता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान को प्रोत्साहित करना है। यह भी बताया गया है कि जब वंदे मातरम का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है, तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए।

एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़ी साजिश मामले में तीन लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की

एजेंसी, अहमदाबाद

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी साजिश मामले में तीन लोगों के खिलाफ अहमदाबाद की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपित जहरीले रसायन के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। मामले का मुख्य आरोपित हैदराबाद निवासी डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, जबकि उत्तर प्रदेश का रहना वाला आजाद और मोहम्मद सुहैल को भी आरोपित बनाया गया है। तीनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून, भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपित विदेश में बैठे आतंकी संचालकों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर देश में दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। आरोपित युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर अपने संगठन से जोड़ने का काम भी कर रहे थे।

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपित डॉक्टर मोहिउद्दीन ने अपने घर में जहरीला पदार्थ तैयार करने के लिए गुप्त प्रयोगशाला बना रखी थी। वह एरंड के बीजों से अत्यंत घातक जहर तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जिसका इस्तेमाल बड़े आतंकी हमले में किया जाना था। यह मामला सबसे पहले गुजरात एटीएस ने दर्ज किया था। नवंबर 2025 में एटीएस ने डॉक्टर मोहिउद्दीन को एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया था। उसकी कार से अवैध हथियार, एरंड का तेल और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई थी।

लखनऊ में 'फ्रूट होराइजन' 7 मई को, शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 मई को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिवराज चौहान 'फ्रूट होराइज़न' से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह दो दिवसीय आयोजन देश में फल उत्पादन, गुणवत्ता, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद किसानों, वैज्ञानिकों, निर्यातकों और अन्य संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर फल क्षेत्र को नई दिशा देना है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ सीधा संवाद करेंगे। शिवराज सिंह की प्रगतिशील निर्यातकों के साथ बैठक होगी, साथ ही निर्यातकों, निदेशकों और अन्य हितधारकों के साथ भी उनकी चर्चा होगी। इस संवाद में फल निर्यात बढ़ाने, बाजार की चुनौतियों को समझने और बेहतर रणनीति बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे देश के फल कारोबार को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में मदद मिलेगी। मुख्य कार्यक्रम आईसीएआर के केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ में होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 7 मई को सुबह 10 बजे से किसानों, पौधशाला से जुड़े लोगों और प्रसंस्करण क्षेत्र के हितधारकों के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का संवाद होगा।

देशभर में घरेलू रसोई गैस का वितरण सामान्यः सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि देशभर में घरेलू रसोई गैस का वितरण सामान्य है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से कोई ड्राई-आउट की खबर नहीं है। सरकार ने कहा कि लगभग 95 फीसदी गैस सिलिंडर का वितरण 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के जरिए पूरी की जा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) का वितरण सामान्य बना हुआ है, और स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 95 फीसदी गैस सिलिंडर का वितरण 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के जरिए पूरा किया जा रहा है। साथ ही पिछले दो दिनों में 88.82 लाख बुकिंग के मुकाबले लगभग 87.28 लाख सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं।

सुजाता शर्मा ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच खाना पकाने के लिए सरकार घरेलू रसोई गैस की 100 फीसदी आपूर्ति उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और कमर्शियल सिलेंडरों के उपभोक्ताओं को 70 फीसदी तक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। संयुक्त सचिव ने बताया कि लगभग 6 लाख 31 हजार नए पीएनजी कनेक्शनों में गैस सप्लाई शुरू हो गई है और 2.67 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 6 लाख 93 हजार उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शनों के लिए रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि 49 हज़ार से जयादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपनी LPG कनेक्शन स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं। सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों में लगभग 15,900 टन कमर्शियल एलपीजी और 876 टन ऑटो एलपीजी की बिक्री दर्ज की गई है। इसके अलावा लगभग 1.2 लाख 5 किलो वाले सिलिंडर भी बेचे गए हैं। वहीं, 3 अप्रैल से अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, जिनके दौरान अब तक 1.84 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलिंडर बेचे जा चुके हैं। शर्मा ने यह भी बताया कि कामकाज और रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से चल रहे हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र के हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि नाविकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और समुद्री परिचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 48 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय नाविकों को ले जा रहे विदेशी ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

अमेरिका-ईरान तनाव में ऐतिहासिक मोड़- युद्धविराम से समझौते की दहलीज तक:युद्ध पर लगेगा ब्रेक? समझौते से संभावित स्थाई शांति की उम्मीद? -बदलती भू- राजनीति का नया अध्याय- समग्र व्यापक विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» वैश्विक ऊर्जा संकट से कूटनीतिक समाधान तक :अमेरिका -ईरान तनाव में ऐतिहासिक मोड़- एमओयू पर सहमति? -48 घंटे पूरी दुनियाँ के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं?

» ईरान-अमेरिका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब पहुँचे,जो वैश्विक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक -यह अवसर चूका तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया की भू-राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है,जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव अब संभावित कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगभग 40 दिनों तक चले तीव्र सैन्य संघर्ष, जिसमें ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक व्यापार मार्गों पर गंभीर प्रभाव पड़ा,ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गहरी चिंता में डाल दिया था। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जो विश्व के लगभग एक-तिहाई समुद्री तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है, संघर्ष का केंद्रीय बिंदु बन गया था। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता ने न केवल तेल की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल पैदा किया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर कर दिया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारत जैसे ऊर्जा आयात- निर्भर देशों के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बन गई, जहाँ महंगाई और चालू खाता घाटे पर प्रत्यक्ष दबाव देखा गया।इसी पृष्ठभूमि में, 8 अप्रैल 2026 को लागू किया गया दो सप्ताह का अस्थायी युद्धविराम एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आया, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान द्वारा इस्लामाबाद में आयोजित वार्ताओं के माध्यम से संभव हुई।यह पहल न केवल क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत थी,बल्कि इसने यह भी दर्शाया कि मध्यम शक्तियाँ भी जटिल वैश्विक संकटों के समाधान में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। 21 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने का निर्णय इस बात का संकेत था कि दोनों पक्ष अब टकराव की बजाय संवाद को प्राथमिकता देने लगे हैं।

इस निर्णय ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता लौटाने और कूटनीतिक प्रक्रिया को समय देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।अब 6 मई 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार,दोनों देश एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने के बेहद करीब पहुँच चुके हैं, जो न केवल वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि एक व्यापक परमाणु समझौते की रूपरेखा भी तय करेगा। यह संभावित समझौता वैश्विक कूटनीति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हो सकता है, क्योंकि यह वर्षों से चले आ रहे अविश्वास,प्रतिबंधों और सैन्य टकराव के चक्र को तोड़ने का अवसर प्रदान करता है। यदि यह पहल सफल होती है, तो यह न केवल पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल करेगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक संतुलन को भी एक नई स्थिर दिशा देगी। साथियों बात अगर हम युद्ध पर लगेगा ब्रेक? ईरान- अमेरिका समझौते की दहलीज पर खड़ी दुनिया में शांति की नई उम्मीद इसको समझने की करें तो 6 मई 2026 की वैश्विक कूटनीतिक तस्वीर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है,जहाँ पिछले कुछ महीनों से मध्य पूर्व में सुलग रही आग अब शांत होने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी 2026 से जारी सैन्य टकराव ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को गहरे संकट में डाल दिया था,बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया था। लेकिन अब जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे इस संघर्ष के संभावित अंत की ओर इशारा करते हैं। दोनों देश एक एक-पन्ने के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमति के करीब पहुँच चुके हैं, जिसे यदि अंतिम रूप मिल जाता है,तो यह 2026 के इस संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। साथियों बात अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलेपहलू को समझने की करें तो यह है कि यह समझौता केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है,बल्कि इसमें दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता के तत्व भी शामिल हैं। प्रस्तावित समझौते के अनुसार, दोनों देश मध्य पूर्व में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा करेंगे,जो पिछले दो महीनों में कई स्तरोंपर बढ़ता गया था। इस संघर्ष के दौरान समुद्री मार्गों पर हमले, ड्रोन स्ट्राइक, और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने की घटनाएँ सामने आईं, जिससे वैश्विक व्यापार मार्गों, विशेष रूप से तेल आपूर्ति, पर गहरा असर पड़ा। ऐसे में युद्धविराम की संभावना अपने आप में एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। साथियों बात अगर हम इस समझौते का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम को समझने की करें तो वह है होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ा मुद्दा।यह जलमार्ग विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है,जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता है। संघर्ष के दौरान इस मार्ग पर नाकाबंदी और हमलों ने तेल की कीमतों को अस्थिर कर दिया था और वैश्विक बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था।अब प्रस्तावित समझौते के तहत दोनों देश इस जलडमरूमध्य को चरणबद्ध तरीके से खोलने और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर सहमत हुए हैं। यह न केवल ऊर्जा बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि वैश्विक व्यापारिक विश्वास को भी बहाल करने में मदद करेगा। साथियों बात अगर हम तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है इसको समझने की करें तो, ईरान ने संकेत दिया है कि वह यूरेनियम संवर्धन को 15 वर्षों तक रोकने और परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव 2015 के परमाणु समझौते की याद दिलाता है, जिसे बाद में अमेरिका ने एकतरफा रूप से छोड़ दिया था। इस बार दोनों पक्ष अधिक सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं।अमेरिका की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि वह ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और उसकी फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियों को वापस करने के लिए तैयार है। यह कदम ईरान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण व बिलकुल सटीक भूमिका निभा सकता है। साथियों हालांकि,इन सभी संभावित समझौते की राह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देशों के बीच कुल 14 मुद्दों पर बातचीत चल रही है, जिनमें से दिनांक 6 को 2026 को केवल 3 पर सहमति बनी है, जबकि 11 मुद्दों पर अभी भी मतभेद कायम हैं। इन मुद्दों में क्षेत्रीय प्रभाव, मिसाइल कार्यक्रम,और निरीक्षण व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषय शामिल हैं। यह स्पष्ट करता है कि भले ही एक प्रारंभिक समझौता निकट हो, लेकिन स्थायी शांति के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही है।उन्होंने एक ओर जहाँ ईरान के खिलाफ कड़े सैन्य और आर्थिक कदम उठाए, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक समाधान की दिशा में भी पहल की। प्रोजेक्ट फ्रीडम नामक नौसैनिक अभियान को अस्थायी रूप से रोकने का उनका निर्णय इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब टकराव की बजाय बातचीत को प्राथमिकता देना चाहता है। हालांकि, ट्रंप के बयानों में अब भी आक्रामकता झलकती है, जैसे उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह द्वंद्वात्मक रणनीति दबाव और संवाद का मिश्रणअमेरिकी विदेश नीति का एक परिचित पैटर्न है। ईरान की ओर से भी लचीलापन दिखाया गया है,जो इस बात का संकेत है कि वह लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष से बचनाचाहता है।आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है, और ऐसे में प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए वह कुछ शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई देता है। हालांकि, ईरान के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखे, जो बातचीत को जटिल बनाता है। साथियों बात अगर हम इस संभावित समझौते का वैश्विक प्रभाव को समझने की करें तो यह है कि अत्यंत व्यापक होगा। सबसे पहले, ऊर्जा बाजारों में स्थिरता आएगी, जिससे तेल और गैस की कीमतों में गिरावट संभव है। इससे उन देशों को राहत मिलेगी जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं,जैसे भारत,जापान और यूरोपीय देश।दूसरा, वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है, क्योंकि युद्ध की अनिश्चितता निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम कारक होती है। तीसरा, यह समझौता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बन सकता है, जहाँ दो विरोधी देश संवाद के माध्यम से समाधान तक पहुँचते हैं। साथियों बात अगर हम इस पूरे समझौते को भारत के संदर्भ में देखेंतो यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है।भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है,और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिरता उसके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।इसके अलावा, भारत के लाखों प्रवासी इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा भी इस संघर्ष से प्रभावित होती है। ऐसे में यदि यह समझौता सफल होता है,तो भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर लाभ होगा। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे समझौते अक्सर नाजुक होते हैं। 2015 का परमाणु समझौता भी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था,लेकिनराजनीतिक बदलावों और आपसी अविश्वास के कारण वह टिक नहीं सका। इस बार भी यदि दोनों पक्ष अपने वादों पर कायम नहीं रहते, तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है।इसलिए इस समझौते की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इसे लागू करते हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि यह कहा जा सकता है कि 6 मई 2026 का यह क्षण केवल एक संभावित समझौते का नहीं, बल्कि वैश्विक शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक है। यदि अमेरिका और ईरान इस अवसर का सही उपयोग करते हैं,तो यह न केवल उनके द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देगा, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य की नींव भी रखेगा। लेकिन यदि यह अवसर चूक गया, तो इसके परिणाम भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं।इसलिए आने वाले 48 घंटे केवल इन दो देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 92262293188

भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक हैं टैगोर

लेखक- योगेश कुमार गोयल

कोलकाता में साहित्यिक माहौल वाले कुलीन धनाढ्य परिवार में 7 मई 1861 को जन्मे रवीन्द्रनाथ टैगोर एक कवि, उच्च कोटि के साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार के अलावा संगीतप्रेमी, अच्छे चित्रकार तथा दार्शनिक भी थे। टैगोर एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 1913 में विश्वविख्यात महाकाव्य 'गीतांजली' की रचना के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि उन्होंने यह पुरस्कार स्वयं समारोह में उपस्थित होकर ग्रहण नहीं किया था बल्कि ब्रिटेन के एक राजदूत ने यह पुरस्कार लेकर उन तक पहुंचाया था। नोबेल पुरस्कार में मिले करीब एक लाख आठ हजार रुपये की राशि टैगोर ने किसानों की बेहतरी के लिए कृषि बैंक तथा सहकारी समिति की स्थापना और भूमिहीन किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनाने में इस्तेमाल की। टैगोर की महान रचना 'गीतांजली' का प्रकाशन वर्ष 1910 में हुआ था, जो उनकी 157 कविताओं का संग्रह है। इसी काव्य संग्रह को बाद में दुनिया की कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया। मार्च 1913 में लंदन की मैकमिलन एंड कंपनी ने इसे प्रकाशित किया और 13 नवम्बर 1913 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इसके दस संस्करण छापे गए। टैगोर की कुछ कविताएं तो बांग्लादेश के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हैं। जहां तक भारत के राष्ट्रीय गीत 'जन गण मन' की बात है कि इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दूसरे दिन का काम शुरू होने से पहले 27 दिसम्बर 1911 को पहली बार गाया गया था। हालांकि उस दौरान इस बात को लेकर भी कुछ विवाद चला कि कहीं उन्होंने यह गीत अंग्रेजों की प्रशंसा में तो नहीं लिखा लेकिन इसके रचयिता टैगोर ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि इस गीत में वर्णित 'भारत भाग्य विधाता' के केवल दो ही अर्थ हो सकते हैं, देश की जनता या फिर सर्वशक्तिमान ऊपर वाला, फिर चाहे उसे भगवान कहें या देव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर राष्ट्रीयता, देशभक्ति, तर्कशक्ति इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग राय रखते थे लेकिन दोनों एक-दूसरे का बहुत सम्मान भी किया करते थे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद टैगोर को गांधीजी ने ही सर्वप्रथम 'गुरूदेव' कहा था जबकि गांधीजी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी। उन्होंने 12 अप्रैल 1919 को गांधीजी को 'महात्मा' का सम्बोधन करते हुए एक पत्र लिखा था, उसके बाद ही गांधीजी को महात्मा कहा जाने लगा। मात्र आठ वर्ष की आयु में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी थी और 16 वर्ष की आयु में कहानियां तथा नाटक लिखना शुरू कर दिया था। बैरिस्टर बनने के सपने के साथ वह 1878 में इंग्लैंड चले गए थे लेकिन दो ही वर्ष बाद डिग्री लिए बिना ही भारत लौट आए। 1901 में सियालदह छोड़कर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांतिनिकेतन में आने के बाद रवीन्द्रनाथ टैगोर ने वहां प्रकृति की गोद में खुले प्राकृतिक वातावरण में वृक्षों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ केवल पांच छात्रों के साथ छोटे से 'शांतिनिकेतन स्कूल' की स्थापना की, जो 1921 में 'विश्वभारती' नाम से एक समृद्ध विश्वविद्यालय बना।। 1919 में उन्होंने शांतिनिकेतन कला के एक स्कूल 'कला भवन' की भी नींव रखी, जो दो साल बाद विश्वभारती विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। शांतिनिकेतन में ही गुरूदेव ने अपनी कई साहित्यिक कृतियां लिखी और यहां मौजूद उनका घर आज भी ऐतिहासिक महत्व का है। उनका ज्यादातर साहित्य काव्यमय रहा और अनेक रचनाएं गीतों के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1880 के दशक में उन्होंने कविताओं की कई पुस्तकें प्रकाशित की और 1890 में 'मानसी' की रचना की। कविता, गान, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला इत्यादि साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा है, जिसमें उनकी रचना न हो। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतांजली, गीताली, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया हैमांति, क्षुदिता, मुसलमानिर गोल्पो आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया, जिसके बाद उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में पढ़ी और सराही गई। उपन्यास में गोरा, चतुरंगा, नौकादुबी, जोगजोग, घारे बायर, मुन्ने की वापसी, अंतिम प्यार, अनाथ इत्यादि गुरूदेव के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तत्वावधान में दिल्ली-एनसीआर की ट्रांसपोर्ट यूनियनों की अहम निर्णय

लोकतंत्र की शान

सी. ए. क्यू. एम और दिल्ली सरकार द्वारा NGT टैक्स में भारी वृद्धि तथा बी.एस. IV कमर्शियल वाहनों पर 01.11.2026 से दिल्ली में प्रतिबंध के विरोध में 21.05.2026 से 23.05.2026 तक दिल्ली एन.सी.आर. के समस्त परिवहन संगठनों द्वारा

तीन दिवसीय सांकेतिक चक्काजाम| ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ए.आई.एम.टी.सी.) भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र के माल एवं यात्री दोनों वर्गों के हितों की रक्षा हेतु वर्ष 1936 से कार्यरत एक शीर्ष संस्था है। एआईएमटीसी लगभग 95 लाख ट्रक चालकों और लगभग 26 लाख निजी बस, टैक्सी एवं मैक्सी-कैब संचालकों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देशभर में फैली लगभग 3500 तालुका, ज़िला एवं राज्य स्तरीय परिवहन संघों एवं यूनियनों की शीर्ष इकाई हैं। डॉ हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष - ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ए.आई.एम.टी.सी.) के नेत्रत्व में 26-04-2026 दिल्ली एवं एनसीआर की सभी प्रमुख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों और यूनियनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में सी.ए.क्यू.एम एवं दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ई.सी.सी.) में की गई भारी बढ़ोतरी तथा बी.एस. IV कमर्शियल वाहनों पर 01.11.2026 से दिल्ली में प्रतिबंध पर विस्तार से चर्चा की गई और इस फैसले के खिलाफ सभी परिवहन संगठनों के पदाधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया और रोष प्रकट किया | डॉ हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष - ए.आई.एम.टी.सी. ने ई.सी.सी. बढ़ोतरी पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की प्रमुख चिंताएं से अवगत करते हुए कहा "सी. ए. क्यू. एम की सिफारिश के अनुसार, जो ट्रक दिल्ली में न तो लोड करते हैं और न ही अनलोड, बल्कि सिर्फ दिल्ली को एक कॉरिडोर की तरह पार करके दूसरे राज्यों में माल लेकर जाते हैं, उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भेजने के लिए इस शुल्क में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था। इसका ए.आई. एम.टी.सी. ने भी समर्थन किया था।" माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश के अनुसार ई.सी.सी. बढ़ाने का उद्देश्य केवल उन ट्रकों को हतोत्साहित करने का था, जो बिना किसी काम के दिल्ली से ट्रांजिट होकर गुजरते हैं | यह व्यवस्था सिर्फ ट्रांजिट वाहनों पर लागू होनी थी, न कि दिल्ली में सामान लाने-ले जाने वाले वाहनों पर, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुचारु बनाने और यहाँ के निवासियों के लिए आवश्यक सामान लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन सी. ए. क्यू. एम और दिल्ली सरकार ने यह ई.सी.सी. बढ़ोतरी सभी वाहनों पर लागू कर दी है, यहां तक कि उन ट्रकों पर भी जो दिल्ली में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए जरूरी रूप से आते हैं और यहां के निवासियों को आवश्यक सामान पहुंचाते हैं। यह ट्रक ऑपरेटर्स के साथ अन्याय और विश्वासघात है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर चोट करती है| सरकार का यह कदम जमीनी हकीकत से दूर है और दिल्ली में आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन पर नकारात्मक असर पड़ेगा |" श्री कुलतारण सिंह अटवाल, अध्यक्ष – फेडरैशन ऑफ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली एव पूर्व अध्यक्ष - ए.आई.एम.टी. सी., ने दिल्ली में कमर्शियल वाहनों पर सी.ए.क्यू.एम व दिल्ली नगर निगम द्वारा पर्यावरण शुल्क (ई.सी. सी.) हल्के कमर्शियल वाहनों (एल. सी. वी.) पर 1400 रुपये से बढ़ाकर करीब 2000 रुपये कर दिया गया है, वहीं भारी ट्रकों के लिए यह शुल्क 2600 रुपये से बढ़ाकर सीधे बताया कि "राजधानी 4000 रुपये तक पहुंच गया है | कुल मिलाकर इस फैसले से 40 से 55 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है| इस फैसले को लेकर देशभर के परिवहन संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और विरोध तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं |" श्री गुंजीत सिंह सांघा, अध्यक्ष – ट्रांसपोर्ट वेल्फेयर सोसाइटी, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर ने कहा "2015 से ई.सी.सी. के नाम पर हमसे करोड़ों रुपये वसूले गए हैं लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं देखने को मिला है| यह करोड़ों रुपये का ई.सी. सी. का दिल्ली में प्रदूषण कि रोकथाम में कहाँ उपयोग हुआ, कुछ पता नहीं |

ई.सी.सी. सिर्फ राजस्व अर्जित करने का माध्यम बन गया है |" डॉ हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष – ए.आई. एम.टी.सी. ने बताया कि "सी. ए. क्यू. एम के संशोधित आदेश संख्या 88 (पत्र क्रमांक फ़. नं. ए-11018/01/2021-सी. ए. क्यू. एम -1430, दिनांक 17.10.2025) के तहत 01 नवम्बर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में बी.एस.-VI, सी.एन.जी. एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत बी.एस.-IV और उससे नीचे के मानकों के कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। बी.एस.-IV एवं उससे नीचे के मानकों के कमर्शियल वाहनों पर लगाए गए इस पूर्ण प्रतिबंध से देश के लाखों छोटे एवं माध्यम वर्ग के परिवहन संचालकों की आजीविका, आर्थिक स्थिति और लॉजिस्टिक प्रणाली पर गंभीर एवं व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उनके परिवारों की आजीविका और भरण-पोषण इस पूर्ण प्रतिबंध से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा| उक्त आदेश अंतर्विरोध से युक्त है, क्योंकि देशभर में बी.एस.-VI वाहन 1 अप्रैल 2020 से लागू किए गए थे। उससे पूर्व बी.एस.-IV वाहन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित थे और उन्हें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 15 वर्षों की वैधता प्रदान की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्षों तक सीमित है|" श्री श्याम सुन्दर, अध्यक्ष – दिल्ली एन.सी. आर. ट्रांसपोर्ट एकता मंच "वर्तमान स्थिति में बी.एस.-IV एवं बी.एस.-VI वाहन, जिनका दिल्ली में कोई कार्य नहीं है, एक्सप्रेसवे के माध्यम से सफलतापूर्वक डायवर्ट हो रहे हैं। बी.एस.-IV वाहन, जो एड-बल्यू तकनीक का उपयोग करते हैं, को स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया गया था। ऐसे वाहनों पर, वैध पी.यू.सी.सी. प्रमाणपत्र होने के बावजूद, दंडात्मक कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि नीतिगत असंगति भी दर्शाती है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के भी विपरीत है, जिसमें बीएस-4 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्षों तक संचालित करने की अनुमति दी गई है| केवल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी के आधार पर बी.एस.-IV वाहनों पर प्रतिबंध लगाना वैज्ञानिक रूप से भी सही तरीका नहीं है और इस विषय पर कोई वैज्ञानिक स्टडी नहीं है। किसी वाहन से निकलने वाला धुआं (प्रदूषण) केवल उसकी उम्र पर नहीं, बल्कि उसके मेक, मॉडल, चले हुए किलोमीटर और उसकी फिटनेस पर भी निर्भर करता है|" श्री मोहन सिंह, अध्यक्ष – राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटरस वलफ़ेयर एसोसिएशन (आर.टी.ओ.डब्ल्यू.ए.) ने कहा कि "हल्के शहरी ट्रैफिक में बी.एस.-IV और बी.एस.-VI डीज़ल वाहनों का प्रदूषण लगभग समान होता है। बी.एस.-IV और बी.एस.-VI दोनों वाहनों में एग्जॉस्ट आफ्टर-ट्रीटमेंट सिस्टम लगे होते हैं। सरकार को कार्रवाई वास्तविक प्रदूषण (टेलपाइप एमिशन) के आधार पर करनी चाहिए, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है, न कि सभी बी.एस.-IV या उससे नीचे के वाहनों पर एकसमान प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस आदेश के लागू होने से 2020–21 मॉडल के बी.एस.-4 वाहनों की आयु प्रभावी रूप से केवल 5 वर्ष रह जाएगी, जो अत्यंत अन्यायपूर्ण है और इससे ईएमआई डिफॉल्ट, आर्थिक संकट, सिबिल स्कोर में गिरावट एवं दिवालियापन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है|" डॉ हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि "पहले से ही महंगाई और बढ़ती ईंधन कीमतों से जूझ रहे ट्रांसपोर्टर्स पर यह निर्णय अतिरिक्त बोझ डालेगा, माल ढुलाई महंगी होने से आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर आम जनता और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर पड़ेगा | उन्होंने जोर दिया कि बी.एस.-VI वाहन अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और प्रदूषण कम करते हैं, इसलिए उन पर ई.सी.सी. लगाना उचित नहीं है। उन्होने कहा कि "दिल्ली एन.सी.आर. के लगभग 62 संगठनों ने भाग लिया और सभी ने गहरी चिंता और रोष व्यक्त करते हुए माना है कि उक्त तुकलकी फरमान से परिवहन व्यवसाय पर, और विशेषकर छोटे व्यवसाइयों पर, गंभीर आर्थिक बोझ पड़ेगा और पूरे व्यापार तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि सी. ए. क्यू. एम और दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर ई.सी.सी. में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया और इसे केवल ट्रांजिट वाहनों तक सीमित नहीं किया गया, तथा बी.एस.-IV वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में 01.11.2026 से प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस नहीं लिया गया, तो दिल्ली-एनसीआर के समस्त परिवहन व्यवसायी 21.05.2026 से 23.05.2026 तक अपना परिवहन कार्य बंद कर सांकेतिक हड़ताल करेंगे। डॉ. हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष - ए.आई. एम.टी.सी. ने बताया कि दिल्ली एन.सी.आर. की समस्त ट्रांसपोर्ट संस्थाएं ट्रांसपोर्ट एकमत हैं कि अगर सरकार उनकीं मांगें नहीं मानतीं तो वे अनिश्चितकालीन चक्का जाम पर जाने पर मजबूर होंगें |

प्रमुख मांगें : दिल्ली गंतव्य वाले ट्रकों या खाली वाहन जो दिल्ली में लोडिंग के लिए आते हैं उन पर बढ़ा हुआ ई.सी.सी. लागू न किया जाए। बढ़ा हुआ ई.सी.सी. सिर्फ ट्रांजिट वाहनों पर ही लागू हो| ट्रांजिट वाहनों की पहचान के लिए स्पष्ट, पारदर्शी और व्यावहारिक व्यवस्था बनाई जाए। बी.एस.-VI वाहनों को ई.सी.सी. से पूरी तरह छूट दी जाए। दिल्ली-एनसीआर में सी. ए. क्यू. एम द्वारा बी.एस.-IV वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को वापस लिया जाए, क्योंकि यह छोटे ऑपरेटरों के लिए अन्यायपूर्ण और आजीविका पर आघात है । वैध पी.यू.सी.सी. धारक बी.एस.-IV वाणिज्यिक वाहनों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत जीवनकाल तक दिल्ली-एनसीआर में संचालन की अनुमति दी जाए चरणबद्ध प्रतिबंध नीति अपनाई जाए - जैसे-जैसे बी.एस.-IV वाहन 10 वर्षों की आयु पूरी करें, वैसे-वैसे उन्हें दिल्ली-एनसीआर से हटाया जाए । डॉ हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉंग्रेस पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसे निर्णय जो लाखों परिवहन संचालकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन्हें संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाना चाहिए।

मोबाइल की चकाचौंध में गुम हुआ बचपन

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

आज की शाम किसी भी मोहल्ले के पार्क या कॉलोनी के पास से गुज़रिए, एक सन्नाटा मिलेगा, वह शोर-शराबा, बच्चों के चहकने की आवाजे, और पकड़म-पकड़ाई के खेल अब न के बराबर दिखते हैं। अगर कुछ बच्चे नजर भी आते हैं, तो अक्सर वे किसी बेंच पर एक साथ बैठे, सिर झुकाए मोबाइल की स्क्रीन में खोए रहते हैं। उनके अंगूठे स्क्रीन पर तेज़ी से चल रहे होते हैं, जहाँ उनका डिजिटल खिलाड़ी मैदान पर बहुत तेज़ दौड़ रहा होता है, लेकिन हकीकत में उनके अपने पैर थमे हुए हैं। यह मंजर आज की उस कड़वी हकीकत को बताता है जहाँ बचपन खेल के मैदानों से कटकर पांच इंच की स्क्रीन में सिमट गया है। 7 मई का दिन पूरी दुनिया में विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तारीखों के हिसाब से देखें तो यह दिन खेलों को बढ़ावा देने का एक मौका हो सकता है, लेकिन समाज के नाते यह दिन हमसे कुछ सवाल पूछता है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हमारे जीवन से मैदान और मिट्टी का रिश्ता टूट रहा है? एथलेटिक्स कोई भारी-भरकम शब्द नहीं है, यह तो हम सबकी बुनियादी फितरत है। दौड़ना, कूदना और अपनी पूरी ताकत से भागना, ये वो चीजें हैं जो एक बच्चा चलना सीखने के साथ ही अपने आप करने लगता है। लेकिन जैसे-जैसे हम आधुनिक सुविधाओं की तरफ बढ़े, हमने बच्चों के भीतर के इस खिलाड़ी को सुरक्षा और पढ़ाई के नाम पर घरों के भीतर कैद कर दिया है । एक दौर था जब गाँव की पगडंडियों पर नंगे पैर दौड़ना या स्कूल के ऊबड़-खाबड़ मैदानों में पसीना बहाना ही दिन की सबसे बड़ी खुशी होती थी। तब न महंगे जूते थे, न कोई खास डाइट और न ही वातानुकूलित जिम। फिर भी शरीर मजबूत रहता था और मन में गजब का उत्साह। आज तकनीक ने हमें सब कुछ दे दिया है, बस वह पसीना बहाने वाला ज़मीन का रिश्ता कहीं पीछे छूट गया है। आज का बच्चा स्कूल की पढ़ाई, भारी-भरकम ट्यूशन और फिर अंतहीन मुकाबलों की ऐसी अदृश्य रेस में दौड़ रहा है, जहाँ वह मानसिक रूप से तो थक जाता है, उसका शरीर सुस्त पड़ा रहता है । जब भी ओलंपिक जैसे बड़े खेल होते हैं, तो नीरज चोपड़ा या हिमा दास जैसे खिलाड़ियों की सफलता पर पूरा देश गर्व करता है। सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। लेकिन क्या एक समाज के तौर पर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? हकीकत यह है कि आज भी मध्यमवर्गीय परिवारों में खेलकूद को पढ़ाई के बाद का काम समझा जाता है। जैसे ही कोई बच्चा हाथ में फुटबॉल या गेंद, बैट उठाता है, माता-पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगती है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया

संजू-कार्तिक की शतकीय साझेदारी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 48वें मैच में मंगलवार (5 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले समीर रिजवी ने स्कोर को 150 के पार पहुंचाया।

कार्तिक शर्मा और संजू सैमसन के बीच 66 गेंद पर 114 रन की साझेदारी की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने 17.3 ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बनाए। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 10 मैच में 10 अंक हो गए हैं। वह छठे नंबर पर रहे। दिल्ली कैपिटल्स के 10 मैच में 8 अंक हैं। वह सातवें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी ने 24 गेंद पर 40 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 गेंद र 38 रन बनाए। पथुम निसांका ने 19, नितीश राणा ने 15, आशुतोष शर्मा ने 14, करुण नायर ने 13, केएल राहुल ने 12 और अक्षर पटेल ने 2 रन बनाए। मिचेल स्टार्क बगैर खाता खोले नाबाद रहे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। अकील होसैन, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह और जेमी ओवरटन ने 1-1 विकेट लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन 52 गेंद पर 87 और कार्तिक शर्मा 31 गेंद पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे। ऋतुराज गायकवाड़ 6 और उर्विल पटेल 17 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अक्षर पटेल और लुंगी एनगिडी ने 1-1 विकेट लिए। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ। काइल जैमीसन की जगह लुंगी एनगिडी को मौका मिला। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में अकील होसैन और गुरजपनीत सिंह की वापसी हुई।

गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले

विनेश को झटका

डोप टेस्ट न कराने पर नोटिस जारी

नई दिल्ली। गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले पहलवान विनेश फोगाट को अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 18 दिसंबर 2025 को प्रतियोगिता से इतर हुए डोपिंग परीक्षण के लिए मौजूद नहीं रहने के मामले में नोटिस भेजा है। पिछले 12 महीनों में यह पहली बार है जब उन्होंने रहने के स्थान संबंधी नियम का उल्लंघन किया है। चार मई 2026 को भेजे गए पत्र में आईटीए ने विनेश को बताया कि 19 जनवरी 2026 को उनके द्वारा दी गई सफाई की समीक्षा करने के बाद छूटे हुए परीक्षण को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड कर लिया गया है।

इस नोटिस में पांच जनवरी 2026 को भेजे गए एक पिछले पत्र का भी जिक्र है, जिसमें परीक्षण के लिए मौजूद नहीं रहने की बात उठाई गई थी और विनेश से इस पर जवाब मांगा गया था। यह नोटिस डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता, लेकिन यह रहने के स्थान संबंधी नियम के तहत एक चेतावनी के तौर पर दिया जाता है। इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ी हर समय अचानक होने वाले डोपिंग परीक्षण के लिए उपलब्ध रहें।

- **विनेश अपने रहने के स्थान को अपडेट करने में नाकाम रहीं**– वह बेंगलुरु से चंडीगढ़ गई थीं, जिससे उनका नियमित रूटीन बिगड़ गया था। एजेंसी ने यह भी ध्यान में रखा कि हाल ही में उनके घर बच्चा हुआ था, जिससे उनकी निजी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। परीक्षण के दौरान विनेश ने कथित तौर पर पूरा सहयोग किया और डीसीओ को बताया कि वह बैठकों के सिलसिले में चंडीगढ़ में मौजूद हैं। हालांकि, आईटीए ने यह फैसला दिया कि अपना कार्यक्रम बदलने के बावजूद विनेश समय पर अपने रहने के स्थान को अपडेट करने में नाकाम रहीं। इसमें बताया गया कि खिलाड़ियों को किसी भी बदलाव के बाद 'जितनी जल्दी हो सके' अपनी जानकारी अपडेट करनी होती है और किसी भी हाल में तय 60 मिनट के समय से पहले।

दो साल तक का प्रतिबंध लग सकता है

यूनाइटेड विश्व रेस्लिंग और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक साल के भीतर तीन बार परीक्षण के लिए मौजूद नहीं रहने या अपने रहने के स्थान की जानकारी देने में चूक होने पर इसे डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ऐसा होने पर खिलाड़ी पर दो साल तक का प्रतिबंध लग सकता है।

घटना 18 दिसंबर 2025 की

आईटीए ने बताया कि यह घटना 18 दिसंबर 2025 को हुई थी। उस दिन एक डोपिंग नियंत्रण अधिकारी विनेश के लिए तय किए गए 60 मिनट के परीक्षण समय के दौरान उन्हें उनके बताए गए स्थान पर नहीं पाया था। डोपिंग रोधी नियमों के तहत 'पंजीकृत परीक्षण पूल' में शामिल खिलाड़ियों को हर दिन सुबह छह बजे से रात 11 बजे के बीच एक घंटे का ऐसा समय बताना होता है जिस दौरान वे बिना किसी पूर्व सूचना के होने वाले डोपिंग परीक्षण के लिए उपलब्ध रहें। हालांकि, आईटीए ने माना कि उस दिन विनेश हरियाणा विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में हिस्सा ले रही थीं।

विनेश के पास 7 दिन का समय

आखिर में यह फैसला सुनाया गया कि इस छूटे हुए परीक्षण को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। आईटीए ने साफ किया कि 12 महीने के अंदर विनेश के साथ स्थान की जानकारी नहीं देने का यह पहला मामला है। विनेश को चार मई से सात दिन का समय दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि यह परीक्षण उनकी लापरवाही की वजह से नहीं छूटा था तो वह इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील कर सकती हैं।

नोटिस में क्या कहा गया

एजेंसी ने कहा कि विनेश ने 18 दिसंबर को या उससे पहले अपने स्थान को बदलने के लिए एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ऐप जैसे दूसरे तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया। नोटिस में कहा गया, 'ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए आईटीए का मानना ??है कि आप यह साबित नहीं कर पाई कि आपकी तरफ से इस चूक में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई या इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी।'

विनेश ने संन्यास लिया वापस

अगर वह ऐसा नहीं करतीं तो यह फैसला आखिरी माना जाएगा। यह घटनाक्रम विनेश के उस ऐलान के कुछ महीनों बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने दिसंबर 2025 में प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी की बात कही थी। इससे पहले 2024 पेरिस ओलंपिक के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में अधिक वजन होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने आरटीपी में दोबारा पंजीकरण करवाया।

नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में लेंगी हिस्सा

यह एक ऐसा ग्रुप है जो खास तौर पर उन बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है जिन्हें प्रतियोगिता से बाहर भी सख्त डोपिंग परीक्षण से गुजरना पड़ता है। गोंडा में होने वाला नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट विनेश की वापसी का पहला टूर्नामेंट है। उन्होंने डब्ल्यूएफआई पर आरोप लगाया था कि वह उन्हें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोक रहा है। बाद में उन्हें यह भी डर सताने लगा था कि कहीं रेफरी उनके साथ भेदभाव नहीं करें।

आईटीए के बारे में जानें

डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने इस ओलंपियन को सुरक्षा और मुकाबले में हिस्सा लेने का पूरा-पूरा मौका देने का भरोसा दिलाया। आईटीए वह संस्था है जो ओलंपिक और दुनिया की दूसरी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में डोपिंग रोधी कार्यक्रमों का संचालन करती है। लुसाने में स्थित आईटीए लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों के डोपिंग रोधी कार्यक्रमों का भी संचालन करती है।

व्यापार

चीन के निवेश पर अब नहीं होगी दिक्कत, 40 क्षेत्रों में एफडीआई को तुरंत हरी झंडी देगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने चीन सहित भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले अन्य देशों से आने वाले विदेशी निवेश के प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी देने के लिए 40 खास क्षेत्रों की पहचान की है। अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रस्तावों पर 60 दिनों के भीतर फैसला ले लिया जाएगा। विदेशी निवेश के नियमों में किए गए नए बदलावों के मुताबिक, सरकार ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान सहित सात पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश के लिए प्रक्रिया तय कर दी है।

भारतीय कंट्रोल जरूरी

हालांकि, शर्त यह है कि जिस कंपनी में निवेश हो रहा है, उसका मालिकाना हक और कंट्रोल हमेशा भारतीय नागरिकों या भारत की ही किसी कंपनी के पास रहेगा। विदेशी निवेश आने के बाद भी भारतीय पक्ष ही मैनेजमेंट में भारी रहेगा। इन 40 क्षेत्रों को छह बड़े हिस्सों में बांटा गया है। कैपिटल गुड्स का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और कंपोनेंट, पॉलिसिलिकॉन वेफर्स, अडवांस बैटरी कंपोनेंट, रेयर अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग। पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले इंसुलेशन और कास्टिंग-फोर्जिंग का सामान, मशीन टूल्स, डिस्प्ले कंपोनेंट (जैसे प्लाज्मा, एलसीडी, एलईडी), कैमरा मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर, स्पीकर और माइक्रोफोन, लिथियम आयन बैटरी, पहने जाने वाले गैजेट्स और रेयर अर्थ मेटल बनाने वाली यूनिट्स।

जमी-जमाई नौकरी छोड़ी तो साथी थे हैरान, जोखिम उठाकर शुरू किया काम

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रतीक तिवारी जयपुर के रहने वाले हैं। कैंसर की वजह से अपने कई प्रियजनों को खोने के बाद उन्होंने जहरीले खान-पान के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। जमी-जमाई नौकरी छोड़कर प्रतीक ने रूफटॉप ऑर्गेनिक फार्मिंग को टारगेट किया। इसके जरिए हर घर को अपनी सब्जियां खुद उगाने के लिए सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। जब मोटी सैलरी और शानदार कॉर्पोरेट करियर छोड़कर वह उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे तो उनके कई साथियों को हैरानी भी हुई। लेकिन, प्रतीक ने तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। इसी के बाद उन्होंने अपने स्टार्टअप की नींव रखी। इसका नाम लिविंग ग्रीन ऑर्गेनिक्स है। यह 'अर्बन फार्मिंग पैक्स' उपलब्ध कराता है। इसमें पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम और एक ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन किट शामिल होती है। अब अपने स्टार्टअप से वह करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। आइए, यहां प्रतीक तिवारी की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

कई साल करते रहे प्रयोग: यह प्रतीक का उद्यमिता में दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले 2003 में उनका पहला स्टार्टअप बाजार की समझ की कमी के कारण नाकाम हुआ था। दोबारा रिस्क लेते समय उनके पास बहुत कम जमा पूंजी थी। लेकिन, उनकी पत्नी ने घर की जिम्मेदारी संभाली।

वह कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं। 2013 से 2015 के बीच प्रतीक ने अपनी छत पर 150 से ज्यादा गमलों और 14 ऑर्गेनिक कम्पोनेंट के साथ प्रयोग किए। दो साल की लगातार कोशिशों के बाद उन्होंने एक 'पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम' (पीएफएस) ईजाद किया।

आज प्रतीक का स्टार्टअप बड़ा अर्बन फार्मिंग बिजनेस बन चुका है। यह स्टार्टअप लोगों को उनके घर की छत पर बिना मिट्टी, ऑटोमैटिक ड्रिप सिंचाई और यूवी प्रोटेक्टेड बैग्स के जरिए सब्जियां उगाने की सुविधा देता है। उनका बिजनेस मॉडल न सिर्फ घरों के लिए है। अलबत्ता, बड़े अस्पतालों, स्कूलों और होटलों के लिए भी है। खास बात यह है कि ये रूफटॉप गार्डन कंक्रीट की छतों को ठंडा रखते हैं। इससे गर्मियों में नीचे के कमरों का तापमान 6 से 7 डिग्री तक कम हो जाता है।

अब करोड़ों की कमाई

प्रतीक के बिजनेस में उतार-चढ़ाव भी आए। वित्त वर्ष 2024-25 में लेबर-इंटेंसिव 'ग्रीन वॉल' बिजनेस के कारण उनका रेवेन्यू काफी गिर गया था। लेकिन, प्रतीक ने हार मानने के बजाय अपने मॉडल को बदला। स्केलेबल अर्बन फार्मिंग पैक्स पर फोकस किया। इससे वित्त वर्ष 2025-26 में उनकी आय 2 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। अब उनका टारगेट फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू करना है ताकि भारत के हर शहर में लोग घर की छत पर केमिकल फ्री, शुद्ध और ताजा सब्जियां उगा सकें।

नौकरी छोड़ने का लिया फैसला

प्रतीक तिवारी ने 1998 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। महिंद्रा, रिलायंस फ्रेश, आईटीसी और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में सप्लाई चेन और रिटेल सेक्टर में अहम पदों पर काम किया। साल 2012 के अंत में जब उन्होंने वॉलमार्ट से रेजिग्नेशन दिया तो उनके साथी हैरान थे। लेकिन, प्रतीक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके परिवार में कैंसर से हुई मौतों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि पैसा सुरक्षा तो दे सकता है। लेकिन, सेहत की गारंटी नहीं। इसी व्यक्तिगत त्रासदी ने उनकी जिंदगी का मकसद बदल दिया।

● कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी, गन्ना का एफआरपी किया तय

हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ताबड़तोड़ फैसले लिए

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। इसके तहत हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। भारत के कपास क्षेत्र में आने वाली बाधाओं, घटती ग्रोथ और क्वालिटी संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ' कपास उत्पादकता मिशन ' (2026-27 से 2030-31) के लिए 5659.22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसी तरह सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए 18,100 करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीजन 2026-27 (अक्टूबर - सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल मंजूर किया है। इसके लिए अलावा और भी कई अहम निर्णय लिए हैं। सोमवार को कई राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद ये फैसले लिए गए हैं। आत्मनिर्भरता और वैश्विक कपड़ा बाजारों

में प्रतिस्पर्धा के लिए 5659.22 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 'कपास उत्पादकता मिशन' को मंजूरी दी है। यह मिशन भारत सरकार के '5स्त्र' विजन (फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से से फैशन तक और फैशन से फॉरेन तक) के अनुरूप है। यह मिशन रोग और कीटों के प्रति प्रतिरोधी 'अधिक उपज देने वाली किस्म' के बीजों के विकास के जरिये कपास की उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके साथ ही, यह राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिये मौजूदा और नवीनतम फसल उत्पादन तकनीकों के बड़े पैमाने पर प्रचार और अपनाने को बढ़ावा देता है। उद्योग को न्यूनतम संदूषण वाला कपास उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। कैबिनेट ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ना किसानों की खातिर 365 रुपये प्रति क्विंटल के 'उचित और लाभकारी मूल्य' को मंजूरी दी है। इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ चीनी मिलों और उनसे जुड़ी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख मजदूरों को भी फायदा होगा। यह मूल्य 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर के लिए 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके तहत, 10.25 प्रतिशत से ऊपर रिकवरी में होने वाली हर 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए 3.56 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा। वहीं, रिकवरी में होने वाली हर 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए 3.56 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाएगी।

भारत ने अमेरिका को चौंकाया, इतना झोंका पैसा कि फटी रह गईं आंखें

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने अमेरिका को चौंका दिया है। भारतीय उद्योगों ने वहां इतना पैसा झोंका है कि अमेरिकियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। 2026 सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट में ऐसा हुआ। इस पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की जोरदार प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे 'बड़ी खबर' करार दिया। साथ ही और डिटेल्स शेयर करने को भी कहा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सर्जियो गोर ने लिखा, 'बड़ी खबर आ रही है! 2026 सेलेक्ट यूएसए समिट में भारत से अमेरिका में भारी-भरकम नए निवेश आ रहे हैं जो हमने अब तक का सबसे बड़ा निवेश देखा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक सच्ची जीत ऐसी ही दिखती है। पूरी जानकारी जल्द ही! इसके पहले अमेरिकी वाणिज्य विभाग में उप-अवर सचिव (नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासन) ब्रैंडन रेमिंगटन ने बताया कि भारत से अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 16.4 अरब डॉलर था। इससे लगभग 70,800 नौकरियों को सहारा मिला। सोमवार मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान आयोजित सीआईआई इंडिया रिसेप्शन को संबोधित करते हुए रेमिंगटन बोले कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी 33 करोड़ डॉलर खर्च किए। रेमिंगटन ने समीक्षाधीन अवधि का कोई जिक्र किए बिना कहा, 'हमें भारत से आपके निवेश का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत से अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल स्टॉक लगभग 16.4 अरब डॉलर था। इससे लगभग 70,800 नौकरियों, रिसर्च और डेवलपमेंट पर 31.3 करोड़ डॉलर के खर्च और 1.5 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात को सहारा मिला। 2023 में जारी सीआईआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में भारतीय निवेश लगभग 40 अरब डॉलर रहा। इससे 4.25 लाख नौकरियों का सृजन हुआ। 2023 में सीआईआई की ओर से जारी 'इंडियन रूट्स, अमेरिकन सॉयल' रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंपनियों ने अमेरिका स्थित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में .1 बिलियन का निवेश किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM
किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)